प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ...सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

जैसे-जैसे आपका विश्वास मजबूत होता जाता है, आपका संदेह खत्म होता जाता है।

गौर गोपाल दास

वर्ष-05, अंक-44 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 03 अगस्त 2023 पृष्ठ-8, मूल्य-5 रुपए

चीफ जस्टिस के सवालों का जवाब नहीं दे पाए सॉलिसिटर जनरल तुषार

नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा से निपटने के राज्य सरकार के तरीके पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और खासतौर पर महिलाओं को निशाना बनाने वाले अपराधों की पुलिस जांच को ÷धीमी÷ करार दिया है। मणिपुर की स्थिति से नाराज शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि वहां कानून-व्यवस्था और संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कोर्ट ने मणिपुर के पुलिस महानिदेशक को 7 अगस्त को तलब किया है।

देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ मणिपुर हिंसा पर दर्ज कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। खंडपीठ ने राज्य सरकार से हत्या, बलात्कार, आगजनी, लूट, घर और संपत्ति, पूजा स्थलों को नुकसान और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले मामलों के बारे में सारणीबद्ध प्रारूप में जानकारी मांगी थी।

मामले में केंद्र का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ से आग्रह किया कि, भीड़ द्वारा महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के वीडियो से संबंधित दो प्राथमिकी के बजाय, राज्य में दर्ज कुल 6 हजार 523 प्राथमिकियों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा से संबंधित सभी 11 मामलों को सीबीआई को सौंपा जा सकता है और मुकदमे की सुनवाई मणिपुर के बाहर कराई जा सकती है।

इस पर सीजेआई ने पूछा कि, कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और कितनी जीरो एफआईआर दर्ज हुई हैं। मणिपुर सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि, कुल 6 हजार 523 प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं लेकिन उन्होंने जीरो एफआईआर का विवरण देने में असमर्थता जताई। सालिसिटर जनरल मेहता इसका भी जवाब नहीं दे पाए कि यौन हिंसा वीडियो से जुड़े मामले में गिरफ्तारी कब हुई...?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो महिलाओं को नग्न कर घुमाने वाला वीडियो वायरल होने और देश भर में आक्रोश फैलने के बाद 20 जुलाई को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पहली गिरफ्तारी की घोषणा की थी।

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि, कोर्ट को यह आभास होता है कि सरकारी मशीनरी इस तरह से खराब हो चुकी है कि आप एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सके। कोर्ट ने कहा कि राज्य पुलिस जांच करने में असमर्थ है। उन्होंने नियंत्रण खो दिया है। जब कोर्ट ने कहा कि 6 हजार एफआईआर में से केवल सात गिरफ्तारियां हुई हैं, तो मेहता ने स्पष्ट करना चाहा कि वायरल वीडियो मामले के संबंध में सात गिरफ्तारियां की गई हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य में अब तक कुल 252 गिरफ्तारियां की गईं हैं।। एसजी मेहता ने कहा कि, 12 हजार निवारक गिरफ्तारियां भी की गई हैं।

कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि, 6 हजार 523 प्राथमिकियों में सिर्फ 252 गिरफ्तारी हुई है। खंडपीठ ने महत्वपूर्ण रूप से यह भी पूछा कि महिलाओं द्वारा यह कहने के बाद कि पुलिस ने उन्हें भीड़ को सौंप दिया था, क्या आरोपी पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई थी। सीजेआई ने यह भी पूछा कि तब डीजीपी क्या कर रहे थे...? उनका कर्तव्य क्या था...?

हंगामे पर भड़के ओम बिड़ला, लोकसभा में आने से कर दिया इनकार...!

नई दिल्ली।
लोकसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू हुए करीब दो सप्ताह का वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक एक भी दिन कार्रवाई सही ढंग से नहीं चल सकी है। मणिपुर, दिल्ली सेवा विधेयक समेत कई मसलों पर विपक्ष का हंगामा जारी है, जिसके चलते किसी भी मसले पर बात नहीं हो पा रही। यही नहीं सत्ता पक्ष भी अपनी शर्तों पर अड़ा है और सदन की कार्यवाही ठप है। इस बीच संसद में हंगामे और वक्त की बर्बादी से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए हैं। उन्होंने लोकसभा में ना आने की बात कही है।

स्पीकर ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बर्ताव पर नाराजगी जताई है। बिरला ने दोनों पक्षों से कहा है कि जब तक सांसदों के व्यवहार में सुधार नहीं आएगा और वे सदन की गरिमा का पालन नहीं करेंगे, तब तक वह लोकसभा में नहीं आएंगे। बता दें कि, हंगामे को लेकर कई बार लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को चेताया था और लगातार अपील की थी कि वे गरिमा का पालन करें।

बुधवार को मॉनसून सत्र का 10वां दिन था, एक ओर जहां पहले ही संसद में मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर हंगामा जारी है। बुधवार की शुरुआत भी राज्यसभा में जबरदस्त हंगामे से हुई। इधर, लोकसभा में भी हंगामे के बाद स्पीकर ओम बिड़ला नाराज हो गए और कामकाज की स्थिति नहीं सुधरने तक वह सदन में नहीं आएंगे।

मोदी सरनेम मामले में दोषसिद्धि पर लगे रोक

नई दिल्ली, एजेंसी।
'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, उन्होंने हमेशा कहा है कि वह अपराध के लिए दोषी नहीं हैं, इसलिए मेरी दोषसिद्धि पर रोक लगे। राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में कहा है कि अगर उन्हें माफी मांगनी होती और सजा को कम कराना होता तो उन्होंने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता।

शिकायतकर्ता ने अहंकारी जैसे शब्द किए इस्तेमाल

राहुल गांधी के हलफनामे में कहा गया है कि, शिकायतकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने जवाब में गांधी का वर्णन करने के लिए 'अहंकारी' शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था।

हलफनामे में आगे कहा गया है कि, राहुल गांधी को बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत परिणाम देना, न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इसे इस अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

कितने कर्ज में है भारतीय रेलवे...? लगातार बढ़ रहा ग्राफ

नई दिल्ली।
यात्रियों का भार उठाने वाली रेलवे खुद भारी कर्जे में डूबी हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ऐसे संकेत दिए हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि, चार वर्षों में रेलवे का कर्ज 8 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गया है। खबर है कि, अधिकारी कर्ज की बढ़ते ग्राफ की वजह बड़े प्रोजेक्ट् को बता रहे हैं। इसके अलावा कोविड के दौरान भी रेल यातायात खासा प्रभावित हुआ था।

एक रिपोर्ट में रेल मंत्री वैष्णव के हवाले से लिखा गया कि, वर्ष 2019-20 में कर्ज 20 हजार 304 करोड़ रुपए का था, जो 2020-21 में बढ़कर 23 हजार 386 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। 2021-22 में आंकड़ा 28 हजार 702 करोड़ रुपए पर था। खबर है कि, रेलवे ने रोलिंग स्टॉक एसेट्स खरीदने और अन्य प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मदद ली है।

कहा जा रहा है कि, 2022-23 में भी रेलवे को कर्ज से राहत नहीं मिली है, बल्कि आंकड़ा बढ़कर 34 हजार 189 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया, हम कई बड़े प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही रेलवे भी कर्ज को कम करने के लिए आंतरिक सेवाओं से राजस्व जुटाने के रास्ते तलाश रहा है।

वित्त मंत्रालय से लिया इतना कर्ज

रेलवे ने 2020-21 में कोविड के दौरान रेलवे की आय में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। तब वित्त मंत्रालय की तरफ से रेलवे को 79 हजार 398 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। इधर, रेलवे का कहना है कि इस कर्ज की वापसी की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2024-25 से शुरू होगी। खास बात है कि रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं भी साथ ही जारी हैं।

हिंदू देवता पर विवादित टिप्पणी कर फंसे केरल विधानसभा अध्यक्ष

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी।
केरल विधानसभा के अध्यक्ष एएन शमसीर द्वारा भगवान गणेश पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई है। केरल विधानसभा अध्यक्ष शमसीर ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि, उनका इरादा कभी भी किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और भगवान गणेश पर उनकी हालिया टिप्पणी पर चल रहा विवाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

विधानसभा परिसर के मीडिया कक्ष में पत्रकारों को संबोधित करते हुए शमसीर ने कहा कि, एर्नाकुलम के एक स्कूल में अपने हालिया भाषण के दौरान उन्होंने एक संवैधानिक पद की क्षमता रखते हुए वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का आग्रह किया और कहा कि किसी को भी अपनी धर्मनिरपेक्ष साख पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है।

नहीं पहुंचाई किसी की भी भावनाओं को चोट

उन्होंने कहा कि, ईमानदारी से सच कहूं तो मैं किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। शमसीर ने दावा किया कि धार्मिक श्रद्धालु उनके साथ हैं और वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने उनके विश्वास और भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाई। उन्होंने कहा कि, मेरा इरादा कभी भी किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। इस मामले पर राज्य में जो हो रहा है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

केंद्रीय सशस्त्र बलों में करीब एक लाख 14 हजार पद खाली

नई दिल्ली, एजेंसी।
केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि, सीआरपीएफ, बीएसएफ और दिल्ली पुलिस जैसे केंद्रीय पुलिस संगठनों में एक लाख 14 हजार 245 पद खाली हैं। केंद्रीय मंत्री मिश्रा ने कहा कि 2023 में लगभग 31 हजार 879 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं और इनमें से एक हजार 126 पद भरे गए हैं।

वर्तमान में लगभग एक लाख से ज्यादा पद खाली

गृह मंत्रालय और उसके संगठन, जिनमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, असम राइफल्स और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केंद्रीय पुलिस संगठन शामिल हैं। उन्होंने एक लिखित उत्तर में कहा कि दिल्ली पुलिस सहित, वर्तमान में लगभग एक लाख 14 हजार 245 पद खाली हैं।

रिक्त पदों में से 3 हजार 75 ग्रुप 'ए' में, 15 हजार 861 ग्रुप 'बी' में और 95 हजार 309 ग्रुप 'सी' में हैं। इनमें से 16 हजार 356 पद अनुसूचित जाति के, 8 हजार 759 पद अनुसूचित जनजाति के, 21 हजार 974 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के और 7 हजार 394 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के और 59 हजार 762 पद सामान्य वर्ग के हैं।

समयबद्ध तरीके से भरे जाते हैं पद

मंत्री ने कहा कि, रिक्त पदों पर भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और जब भी रिक्तियां आती हैं तो पदों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं। मंत्रालय रिक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से भर्ती प्रगति की समीक्षा करता है। मिश्रा ने कहा कि पद समयबद्ध तरीके से भरे जाते हैं।

नूंह में हुई हिंसा को लेकर गुरुग्राम सांसद ने पीएम मोदी से की मुलाकात

नई दिल्ली, एजेंसी।
हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने बुधवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। हरियाणा में 31 जुलाई को सांप्रदायिक झड़प के बाद अभूतपूर्व तनाव है। ये तनाव गुरुग्राम सहित हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया है।

नूंह और सोहना से गुरुग्राम तक पहुंची 2 दिनों की हिंसा में 6 लोगों - 2 होम गार्ड और 4 नागरिकों की मौत हो गई है। सोमवार को नूंह में हिंदू रैली से शुरू हुई हिंसा में कुल 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

गोरक्षक मोनू मानेसर और उसकी टीम के लोगों की रैली में मौजूद होने का दावा करने वाले वीडियो वायरल होने के बाद मुसलमानों ने रैली पर हमला कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में वीएचपी-बजरंग दल ने भी गुरुग्राम की एक मस्जिद पर हमला किया।

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने नूंह हिंसा पर पीएम मोदी से बात की, मंत्री ने कहा कि उन्होंने कई मुद्दों पर पीएम से बात की, हालांकि वह हरियाणा में एम्स के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित करने गए थे।

धार्मिक रैली में लाठी और तलवारें कौन लेकर आता है, इस पर अपनी पिछली टिप्पणी पर सांसद ने कहा, अगर दोनों पक्ष हथियार ले जा रहे थे, तो यह जांच का सवाल है कि उन्हें ये हथियार किसने मुहैया कराए। हरियाणा सरकार इसकी जांच करेगी।

बजरंग दल की साजिश या गलती...?

जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को हिंसा के पीछे एक साजिश को जिम्मेदार ठहराया, वहीं उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो कि भाजपा की सहयोगी जेजेपी से हैं उन्होंने, तनाव के लिए रैली के आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया। दुष्यंत ने कहा कि आयोजकों ने रैली के बारे में, इसमें आने वाले लोगों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी और इससे तनाव पैदा हुआ।

दुष्यंत ने कहा कि मेवात, जिसे अब नूंह के नाम से जाना जाता है, के लोग हमेशा भारत के साथ मजबूती से खड़े रहे और उन्होंने मुगलों के खिलाफ और आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ी।

दिल्ली में विहिप

चूंकि वीएचपी और बजरंग दल बुधवार को दिल्ली में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया, जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया। शीर्ष अदालत ने रैलियों को रोकने से इनकार कर दिया था लेकिन राज्यों को नफरत फैलाने वाले भाषण के खिलाफ कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

आम चुनाव में हुई गड़बड़ी...! प्रोफेसर के रिसर्च पेपर पर मचा बवाल

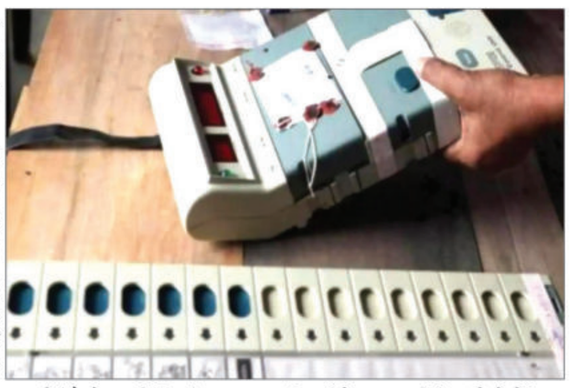

नई दिल्ली।
अशोका यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी के रिसर्च पेपर को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी मेंबर द्वारा पब्लिश कराए गए रिसर्च पेपर में दावा किया गया है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने गड़बड़ी करवाई थी जिसकी वजह से उसे बड़ी जीत हासिल हुई थी। हालांकि विश्वविद्यालय ने रिसर्च पेपर में किए गए दावे से पल्ला झाड़ लिया है।

विश्वविद्यालय की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि, इस रिसर्च पेपर में किए गए दावे किसी स्टाफ या फिर स्टूडेंट के निजी हो सकते हैं। इसका विश्वविद्यालय से कोई लेना देना नहीं है। विश्वविद्यालय के जर्नल में इसे जगह भी नहीं दी गई है।

विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने वाले सब्यासाची दास ने 50 पेज का रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें चुनाव प्रणाली और भाजपा पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी विवाद छिड़ गया है। इस रिसर्च पेपर में कहा गया है कि करीब मुकाबले वाले क्षेत्रों में भाजपा की असंगत जीत चुनाव के वक्त उन राज्यों में भाजपा के शासन की वजह से हुई है। उनका कहना है कि जहां भाजपा की सरकार थी उन्हीं राज्यों में देखने को मिला है कि क्लोज फाइट वाली सीटों पर भाजपा जीत गई। उनका दावा है कि बूथ लेवल पर गड़बड़ी की गई। रिसर्च पेपर में यह भी कहा गया कि जिन जगहों पर भाजपा शासित राज्यों के अधिकारियों की संख्या ऑब्जर्वर के रूप में ज्यादा थी वहां भाजपा की जीत हुई।

छिड़ गई राजनीतिक बहस

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा चुनाव आयोग औरभारत सरकार को इन दावों का जवाब देना चाहिए। उन्हें डीटेल में जवाब देना चाहिए। एक सीरियस स्कॉलर द्वारा दिए गए तर्क कोई राजनीतिक विद्वेष की वजह से नहीं हैं। असंगत वोट टैली के बारे में भी जवाब देने की जरूरत है। इससे भागा नहीं जा सकता।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस रिसर्च पेपर पर सवाल उठाते हुएकहा कि, भाजपा से मतभेद होना गलत नहीं है लेकिन यह तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कोई कैसे आधी रिसर्ट के दम पर देश की चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सकता है। कोई विश्वविद्याल इसकी इजाजत कैसे दे सकती है? इसका जवाब देना चाहिए। विश्वविद्यालय ने जवाब देते हुए कहा कि यह रिसर्च पेपर अभी पूरा नहीं हुआ है और इका क्रिटिकल रिव्यू भी नहीं किया गया है। इसे अकैडमिक जर्नल में भी प्रकाशित नहीं किया गया।

इस रिसर्च पेपर का शीर्षक 'डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी' है। इसमें 2019 के चुनाव को लेकर तर्क दिए हैं कि किस तरह से पैटर्न असंगत था और यह वहां पर हुआ जहां भाजपा की सरकार थी। इसमें यह भी दावा किया गया कि इलेक्शन ऑब्जर्वर द्वारा ढील दी गई जिससे मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया गया।

अधूरा निर्माण बताकर बचने बचाने वाले अधिकारी खुद चलवा रहे है पोकलेन

मनरेगा के नाम पर गुमराह कर रहे अधिकारी, उपयंत्री अहिरवार पर आखिर कब होगी कार्रवाई

माही की गूंज, पेटलावद।

गत दिनों ग्राम पंचायत झोंसर में फूटा मनरेगा अंतर्गत तालाब में जनपद के अधिकारियों का दोहरा रवैया सामने आया है। एक और निर्माण को अधूरा और प्रगति पर बताकर भ्रष्टचार को दबा कर घटिया निर्माण करने वालो के विरुद्ध कार्रवाई नही की गई। वही दूसरी और नियम के विरुद्ध मनरेगा के चलते काम मे पोकलेन मशीन से काम करवा कर खुद के कहे से बदल गए। यहां खुद बचने और बचाने की योजना को अंजाम देते नजर आ रहे है। जहां ग्राम पंचायत में फूटे तालाब को रिपेयरिंग के लिए पोकलेन मशीन लगाई गई और उस तक कोई पत्रकार या जांच दल नही पहुच पाए उसके लिए रास्ते पर पूरी व्यवस्था की गई। दूसरी जनपद के जिम्मेदार अधिकारी इस रिपेयरिंग को लीगल बताकर उनकी जानकारी में काम होना बता रहे है। जनपद सीईओ राजेश दीक्षित को जब तालाब पर पोकलेन चलने की जानकारी दी गई तो उन्होंने साफ कहा कि, जिनकी लापरवाही से तालाब फूटा है सही भी उसे ही करवाना है वो मशीन से करवाये की मजदूर से जब कार्य अपूर्ण होंने की बात कही गई तो साहब पल्ला झाड़ते हुए मशीन चलाने को सही बताने लगे और सब कुछ उनकी जानकारी में होना बताया और तालाब फूटने के पीछे अतिवृष्टि और वेस्टवेयर छोटा बनाया जाना बताया। जबकि ग्राम पंचायत बामनिया में गत वर्ष तालाब पूर्ण होने और भुगतान होने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा रिपेयरिंग के लिए लगाई गई जेसीबी को प्रशासन ने जप्त कर लिया था। अब प्रशासन का दोहरा रवैया समझ से परे है कि, जब घटिया निर्माण की पोल खुली तो उस पर कार्यवाही करने की बजाए उसे दबाया गया और अब भ्रष्टचार दबाने के लिए मनरेगा के कार्य को मशीनों से पूर्ण करवाया जा रहा है।

जिम्मेदार उपयंत्री पर आखिर क्यों मेहरबान अधिकारी, पानी भराव का लेवल हुआ कम

पूरे मामले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी का कार्य उपयंत्री अहिरवार का था जिसकी देख रेख में लापरवाही की गई। इससे पूर्व भी लगातार शिकायते आती रही है लेकिन कमीशन की बंदरबांट के चलते कोई बड़ी कार्यवाही आज तक नही हो पाई। जो स्वतः ही अधिकारीयो की मिलीभगत का प्रमाण है। जिस मात्रा में पानी इस तालाब में भरा जाना था वो नही रह गया और केवल कागज पर निर्माण को पूर्ण बताकर बाकी की राशी निकाल ली जाएगी। फूटे तालाब के हिस्से को बन्द कर वेस्टवेयर को अधिक खोद कर पानी निकाल दिया गया, ताकि भविष्य में अधिक बारिश होने पर अधिक पानी के दबाव से तालाब नही फूटे। तालाब में जमा पानी की मात्रा और स्टीमेट अनुसार तालाब में पानी की क्षमता की जांच होनी चाहिए।

तालाब पर पोकलेन के जरिये होता कार्य।

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित

माही की गूंज, झाबुआ।

कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा की अध्यक्षता में फोटो निर्वाचक नामावली 2023 के प्रारूप प्रकाशन किये जाने के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई है, बैठक में बताया गया कि, बीएलओ द्वारा घर-घर जा कर किये गये सत्यापन, मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण पुनर्व्यवस्था, निर्वाचक नामावली में धुंधली, खराब गुणवत्ता और विनिर्देशन और गैर-मानवीय छवियों को प्रति स्थापित कर, अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरों को सुनिश्चित करते हुए छवि गुणवत्ता में सुधार एवं खण्ड, भागों की पुनर्रचना और मतदान केन्द्रों के खण्ड, भाग की सीमाओं के स्थान के प्रस्तावित पुनर्गठन का अंतिम रूप, मतदान केन्द्रो की सूची एवं कन्ट्रोल टेबल का अवलोकन किया गया।

बैठक में निर्वाचन नामावली के प्रारूप का प्रकाशन कर 31 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियादर्ज करने को कहा गया। इसी के साथ 12,13, 19 एवं 20 अगस्त को विशेष कैंप आयोजित किया जाएगा। 22 सितम्बर तक दावे एवं आपत्तियों का निराकरण के निर्देश दिए गए। 29 सितम्बर तक नामावली के हेल्थ पैरामीटर की जाँच कर अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग से अनुमति प्राप्त करने एवं डाटाबेस को अपडेट कर परिशिष्टो को मुद्रित करने को कहा गया। इसी के साथ बताया गया कि, 4 अक्टूबर को निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

श्रावण मास में सतत् किया जा रहा पारायण पाठ

माही की गूंज, थांदला।

मलुकदास रामायण मण्डल 60 वे श्रावण मास पारायण का शुभारम्भ बुधवार को श्री बडे रामजी मंदिर से किया गया। मण्डल के संरक्षक पं. किशोर आचार्य व ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि, प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी घर-घर मे रामायण पारायण का आयोजन मण्डल द्वारा किया जा रहा है। चुकि इस वर्ष श्रावण मास मे अधिक मास होने की वजह से सतत् दो माह मास पारायण किये जा रहे है। मण्डल द्वारा बुधवार एकम से पूर्णिमा तक मास पारायण पाठ किया जाना है, मण्डल सदस्यो ने सभी सनातन धर्मालंबियो से मास पारायण का लाभ लेने का अनुरोध किया है।

जिले में श्री अन्न फसलों को बढ़ावा, कृषकों और आमजन का रूझान

श्रम साध्य व्यक्तियों के लिये श्री अन्न युक्त भोजन बेहतर विकल्प

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले की जलवायु और भौगोलिक दृष्टि के मद्देनजर कृषक समुदाय द्वारा अपनी खाद्य और पौषणीय आवश्यकताओ की आपूर्ति के लिये फसल चक्र में मिलेट्स फसलों को युक्तियुक्त स्थान दिया जाता रहा है। कालान्तर में नवीन फसलों के चलन में आने तथा आमजन की भोजन शैली में परिवर्तन के कारण मिलेट्स फसलों का क्षेत्र और उनके प्रति रूझान में आंशिक कमी परिलक्षित हुई। किन्तु तथा-कथित आधुनिक भोजन शैली के चलते आमजन की पोषणीय आवश्यकताओ की आपूर्ति में असंतुलन के कारण लघु धान्य जैसी फसलों की ओर पुनः रूझान बढना प्रारंभ हुआ है। लघुधान्य और कदन्न फसल उत्पादों का अपने विषिष्ट पोषणीय गुणों के कारण आमजन की बदलती हुई जीवन शैली के बीच पुनः अपना स्थान रेखांकित हो रहा है। मानव जीवन में मिलेट्स फसलों की अपरिहार्य महत्ता के कारण भारत सरकार के प्रयासो से इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। आमजन को कम लागत में बेहतर पोषणीय तत्वों से युक्त खाद्य प्रदार्थ उपलब्ध कराने की सामर्थ्य के कारण लघु धान्यों को अब श्री अन्न के नाम से भी पहचान स्थापित हो रही है।

जिले के कृषकों को प्रचलित फसलों के स्थान पर श्री अन्न फसलों की ओर आकर्षित करने के लिये रणनीतिक प्रयास भी किये जा रहे है। इस दिशा में जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर समीक्षा और परामर्श के फलस्वरूप लघु धान्यों की बेहतर पैदावार देने वाली किस्मों के बीज कृषकों को उपलब्ध कराये गये है, ताकि आने वाले समय में उन्नत किस्मों का बीज जिले की सीड चेन में स्थापित हो सके। झाबुआ की किसानी में राला फसल का परम्परागत रूप से विषिष्ट स्थान रहा है। जिले की हल्की ढालयुक्त भूमि का अधिकांश क्षेत्र होने के कारण राला फसल की खेती सुविधाजनक तरीके से की जा सकती है। इसके मद्देनजर कृषि विभाग द्वारा राला की उन्नत प्रजाति का बीज रानापुर ग्राम मदनकुई के किसान भटेसिंह दिता को उपलब्ध कराते हुऐ फसल प्रदर्शन आयोजित कराया गया।

जिले के ग्रामीण समुदाय की पारम्परिक भोजन शैली में राला की दलिया के रूप में सेवन प्रमुखता से स्थापित रहा है। राला की दलिया महत्वपूर्ण खनिज लवणों, फाईबर से भरपूर होने के कारण शारीरीक श्रमयुक्त कार्य करने वाले तथा आधुनिक भोजन शैली अपनाने वाले व्यक्तियों के लिये अपनी विशिष्ट महत्ता रखता है। राला में पाये जाने वाले कई तत्व ऐसे है जो उच्च एंटीऑक्सीडेंट की श्रेणी में आते है और ह्दय रोग, कैंसर जैसी बीमारीयों को नियंत्रित करने में लाभकारी होते है।

कृषि अवसंरचना समीक्षा बैठक में प्राकृतिक खेती एवं मिलेट्स फसलों के रकबे में वृद्धि करने पर जोर दिया

माही की गूंज, झाबुआ।

कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा की अध्यक्षता में कार्यालय कलेक्टर कक्ष में कृषि अवसंरचना समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला परियोजना प्रबंधक ग्रामीण अजिविका परियोजना को निर्देशित किया कि, कृषको स्वावलम्बी बनाने के लिये कृषि के साथ अतिरिक्त आय हेतु जिले के कृषको को कृषि के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण तथा मानव स्वास्थ्य बनाये रखने हेतु अजिविका परियोजना के माध्यम से जिले के एनिमिया ग्रसित महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों के लिये न्यूट्रीशन चार्ट तैयार करने के साथ ही आगनवाडी केन्द्रों तथा महिला समूहो के यहाँ उद्यानिकी विभाग से समन्वय स्थापित कर खेतों की मेडो पर 5-5 सुरजना (मुलगा) के पौधों का रोपण करने के साथ ही तुलसी के बीज से पौध तैयार कराकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। प्रति सदस्य 15 से 20 तुलसी पौध रोपण का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा गया।

डीडीएम. नाबार्ड को एग्री इन्फास्ट्रक्चर फण्ड में संचालित विभिन्न गतिविधियों में आनलाईन आवेदन कराने तथा निरस्त किये गये आवेदनों के संबंध में संबंधित हितग्राही तथा बैंक से सम्पर्क कर निराकरण कराने के निर्देश दिये गये साथ ही एफपीओ के व्यवसाय योजना के लिये टर्नओवर बढाने का प्रयास करने तथा इक्विटी अनुदान तथा अगामी कार्य योजना आदि जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। किसानों के हित में जिले में किसानों को स्मार्ट खेती के तहत अधिक से अधिक किसानों के यहाँ ग्रीन हाउस शेड नेट की स्थापना कराई जाकर नवीन उन्नत तकनीक के माध्यम से खेती कराई जाये।

साथ ही कड़कनाथ मुर्गे को बढ़ावा देने हेतु अधिक से अधिक महिला समूहो को क्लस्टर में कृषक उत्पाद संगठन एवं एनजीओ के माध्यम से कड़कनाथ मुर्गीपालन कराये जाने हेतु कन्जेस के माध्यम से हेचरी मशीन का ऋय कराया जाये तथा किसानो का चयन कर उनको कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिये गये। जिले में मछ्ली पालन को बढ़ावा देने हेतु लघु एवं सीमांत किसानों को समूह में छोटे-छोटे पौण्ड/तालाबों में मछ्ली पालन तथा भीगा पालन कराने जाने हेतु चयन किया जाये तथा उन्हें मछ्ली के बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

मतदाताओं को जागरूक करने, जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

माही की गूंज, झाबुआ।

आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदाताओ को अधिक से अधिक मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता वाहन को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री तन्वी हुड्डा, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती रेखा राठौर एवं अपर कलेक्टर एस.एस. मुजाल्दा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वाहन के द्वारा 31 अगस्त तक प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाएगा।

कलेक्टर ने बताया कि, 31 अगस्त तक सभी विधानसभा क्षेत्र में एक-एक रथ जा रहे है। जिसके माध्यम से ईवीएम की जागरूकता को लोगो तक ले कर जा रहे है। इसके द्वारा लोगो को बताया जाएगा कि, किस प्रकार ईवीएम कार्य करती है, किस प्रकार हम अपने मत का प्रयोग कर सकते है। जिससे लोग अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करे।

जिले में प्रतिदिन भीड़-भाड़ वाली जगहों एवं साप्ताहिक हाट बाजार में भी प्रचार रथ के द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाएगा। प्रचार रथ का निर्माण म ध्य प्र दे श माध्यम द्वारा तैयार डिजाईन के अनुसार वाहन में ह ा इ रि सा ल्यू वे शन फ्लेक्स के साथ ही प्रचार रथ में एलईडी वीडियो वॉल लगाई गई है । जिससे अधिक से अधिक लोग मतदान के प्रति जागरूक हो सके।

नवीन पुल निर्माण के बाद, हुई कायाकल्प रोड़ विकास कार्यों की शुरुआत

माही की गूंज, थांदला।

नगर के प्रमुख दो पुल उद्घाटन के बाद तीसरे दौर में मुख्यमंत्री शिवराज सरकार द्वारा प्रदान कायाकल्प के रोड का भूमि पूजन संपन्न हुआ। कुल 52.50 लाख की लागत के 3 रोड स्वीकृत हुए। वार्ड क्रंमाक 6 जहां पर पिछले 13 वर्षों से पेवर्स लगे थे जो जगह-जगह से उखड़ गए थे नगर में नई पाइप लाइन डालने के कारण गड्डे पड़ गए थे, वहां रोड का भूमि पूजन हुआ।

गौरतलब है कायाकल्प अभियान के तहत नगर के तीन रोड गाईड लाइन के अनुसार लिए गए हैं। जिसमें मां पद्मावती नदी के पास वार्ड नंबर 11, 12, 13 जाने वाले मार्गो को जोड़ने वाला एक प्रमुख रोड लिया गया है और मुक्तिधाम वार्ड नंबर 14 में जो बच्चों का मुक्तिधाम है वहां पर रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत वार्ड 6 में भूमि पूजन हुआ। जिसमे प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कलसिंह भाभर ने भूमि पूजन करते हुए कहा कि, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक वार्ड में ऐसे रोड का निर्माण करेगी और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुनील पणदा ने बताया कि, कायाकल्प अभियान के बाद अधोसरंचना योजना के स्वीकृति डेढ़ करोड़ के विकास कार्य नगर में किए जाएंगे। जिसमे शेष वार्डो में रोड एवं क्षतिग्रस्त नाले एवं नालियों को प्राथमिकता से लिया जाएगा।

भूमि पूजन में वार्ड पार्षद एवं जिला शिकायत बोर्ड सदस्य माया सचिन सोलंकी, पार्षद धापू वसुनिया, पार्षद एवं मंडल अध्यक्ष गोलू उपाध्याय, महामंत्री सुनील पणदा, मंडल उपाध्यक्ष एवं पार्षद जितेंद्र राठौर, जगदीश प्रजापत, राजू धानक जनपद सदस्य यशवंत बामनिया, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष आरती सिसोदिया, अजा मोर्चा मंडल अध्यक्ष गोलू फतरोड़, मोहम्मद बोहरा वरिष्ठ नेता किशोर आचार्य पिछड़ा मोर्चा के मंडल महामंत्री दीपक राठौड़ वार्ड प्रतिंनिधि समाजसेवी सचिन सोलंकी और अमित शाहजी, शुभम नागर, गोलू वर्मा एवं वार्ड वासी उपस्थित रहे ।

पालघर में हुई घटना को लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौपा ज्ञापन

माही की गूंज, भानपुरा।

विगत 31 जुलाई को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के समीप सुबह यात्री गाड़ी में हुई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी सहित तीन यात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें भानपुरा निवासी कादर भाई पिता मोहम्मद हुसैन बोहरा भी थे, जो वर्तमान में मुंबई में ही निवासरत थे एवं मोहर्रम पर्व मनाने के लिए भानपुरा आए हुए थे एवं वापस मुंबई लौटने के दौरान ट्रेन में यह घटना घटित हो गई। इस घटना को लेकर बोहरा समाज, मुस्लिम समाज भानपुरा एवं नगर वासियों द्वारा बुधवार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसील कार्यालय भानपुरा में तहसील के बेनी प्रसाद मरावी को ज्ञापन सौंपा गया। सौपे गए ज्ञापन में बताया गया कि, 31 जुलाई को महाराष्ट्र के पालघर में हुई गोलीकांड की घटना में भानपुरा नगर के बोहरा समाज सदस्य कादर भाई पिता मोहम्मद हुसैन एवं अन्य मुस्लिम समाज के बंधुओं तथा पुलिस कर्मचारी टीकाराम मीणा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिससे संपूर्ण बोहरा समाज भानपुरा में आक्रोश व्याप्त है और बोहरा समाज, मुस्लिम समाज एवं भानपुरा वासी इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं एवं ज्ञापन में मांग की गई कि, गोलीकांड की घटना में मृतक कादर भाई एवं अन्य सभी मृतकों के परिजनों को एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता व परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई एवं दोषी हत्यारे को फांसी की सजा दी जाने की मांग की गई। ज्ञापन का वाचन एडवोकेट इरफान अंसारी ने किया। ज्ञापन सौपे जाने के दौरान अंजुमन कमेटी सदर मोहसिन कुरेशी, बोहरा समाज सदर खोजीम भाई बोहरा, शब्बीर भाई, कुतुबुद्दीन हुसैन बोहरा, युसूफ भाई बैंक वाले, हुसैनी भाई, बुरहानी भाई, मुर्तजा बोहरा, मुस्तफा भाई, हुसैन भाई, शेख असलम, एहसास मंसूरी, शकील कुरेशी, सज्जाद कुरेशी, मेहफूज खान, अकील कुरैशी सहीत कई लोग उपस्थित थे।

25 लाख से बना रोड ग्रामीणों के नहीं आ रहा काम, केवल मशीनों से डाला मोर्रम

माही की गूंज, पेटलावद।

मनरेगा योजना में किस कदर भ्रष्टचार हावी है उसका एक और नमूना देंखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायतों और आरईएस विभाग द्वारा बनाई जा रही सदुर सड़क और जीएसबी मार्ग निर्माण कर ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की सुविधा देने का काम सरकार कर रही है। लेकिन उक्त सड़के जमीन पर कम और कागजों पर ज्यादा बनी हुई है। ज्यादातर सड़के केवल खानापूर्ति के लिए स्टीमेट के विपरीत बनी है। जिसमें पानी की निकासी, सड़क के बेस में बोल्डर पत्थर और ऊपरी हिस्से चुरी आदि कुछ नहीं बिछाई जाती, जिसके चलते बारिश में ये सड़के पूरी तरह से बेकार हो जाती है और ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन जाती है। ग्राम पंचायत बेड़दा के चारनपुरा गाँव के ग्रामीण वर्तमान में ऐसी ही गम्भीर समस्या से जूझने पर मजबूर है। जहां रोड़ नही होने से भी अधिक समस्या रोड बनने के बाद भुगत रहे है। ग्राम के दिनेश गरवाल ने बताया कि, उक्त सड़क आरईएस विभाग द्वारा

लगभग 25 लाख की लागत से कोरोना की दूसरी लहर के समय लगभग 3 वर्ष पूर्व ग्राम चारनपुरा के स्कूल से सिंगदेवी माता मंदिर तक बनाई गई थी। उक्त सड़क पर हम ग्रामीणों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है और हर बारिश में हम शिकायत करते है पर इसका कोई निराकरण नहीं हो पाया।

मशीनों से हुआ कार्य, बोल्डर पत्थर और चुरी गायब

गांव के दिनेश गरवाल ने बताया कि, कोरोना कॉल में बनी जीएसबी सड़क पूरी तरह से भ्रष्टचार की भेंट चढ़ चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि, सड़क निर्माण के दौरान भारी मशीनों से मोहर्रम खोद कर बिछा दिया गया। न बोल्डर पत्थर डाले न ही ऊपर पेच वर्क कर चुरी बिछाई गई। पानी की निकासी नही होने से पूरा मार्ग कीचड़ में तब्दील हो गया है। जिससे रहवासियों को आने-जाने में परेशानी हो रही है और वाहन भी फस रहे है।

समाजसेवी शर्मा ने नगर परिषद को भेंट किया शव वाहन

माही की गूंज, थांदला।

लंबे समय से नगर के समाजसेवी शव वाहन हेतु प्रयास कर रहे थे, जिसकी आवश्यकता भी है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इस समस्या का सामना करने में तब अधिक परेशानी आती थी जब उनको अपने परिजनों के शव को कहीं से लाना ले जाना होता था। आज उनकी पीढ़ा को समझते हुए उद्योगपति, समाजसेवी चुन्नू शर्मा ने थांदला एसडीएम तरुण जैन के माध्यम से नगर परिषद को शव वाहन प्रदान किया। इस अवसर पर नगर परिषद सहित, समाजसेवियों और बल्ड डोनेशन टीम ने उनका स्वागत कर आभार प्रदर्शित किया। इस अवसर पर समाजसेवी अनिल भंसाली, गगनेश उपाध्याय, मोहन ब्रजवासी, विनीत शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील पणदा, भाजपा मंडल अध्यक्ष गोलू उपाध्याय, मेघनगर नगर परिषद अध्यक्ष कमलेश मचार, पार्षद जितेंद्र राठौर, जगदीश प्रजापत और बल्ड डोनेशन टीम के अध्यक्ष अजय सेठिया, संरक्षक प्रशांत उपाध्याय उपस्थित रहे।

राष्ट्रीकृत बैंक होतें हुए भी आये दिन होते हैं छोटे खातेदार परेशान

माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

ग्राम में एक मात्र राष्ट्रीकृत यूनियन बैंक में अक्सर सर्व डाउन के चलते लोगों के काम काज ठप रहतें है। खातेदार सुबह बैक में अपने काम काज के लिए जाते हैं तो उन्हें बेक के गेट पर ताला लगा मिलता है। जब किसी भी बैक कर्मचारियों से पुछा जाता है, तो एक ही रटा-रटाया जवाब मिलता है बैक का सर्वर डाउन है। जब पुछा जाता है कब तक चालु होगा तो कर्मचारी कहते हैं कुछ कह नही सकते ऐसा जवाब मिलता है। ग्राहक अपनी पुजी बैक में जमा करता है ताकि समय आने पर उसे बैक से उसकी पुजी तत्काल समय पर मिल जाये। परन्तु ग्राम में राष्ट्रीकृत एटीएम वाली एक मात्र बैक युनीयन बैक जिसमे सात दिन से सारे काम सर्वर के चलते बन्द पड़े हैं। ग्राहक बैक में खाता नहीं खुला पा रहा है, न ही चेक बुक ले पा रहा है, न ही अपना खाता बन्द करा पा रहा है। उपभोक्ता को लेन-देन की भी काफी समस्या आ रही है। सुत्रों के अनुसार खाता खुलवाने के लिए भी उपभोक्ता को कियोस्कों सेंटर पर भेजा जाता है और कियोंस्को संचालकों द्वारा तीन-तीन सौ रुपए लिए जाते हैं। जब की यह पुरी प्रक्रिया बैंक में ही निःशुल्क बैंक द्वारा की जाना चाहिए थी मगर ऐसा नहीं हो रहा है। क्या ऐसा ही चलता रहेगा..? निःशुल्क खातें का भी शुल्क खातेदारों को देना पड़ेगा या बैंक प्रबंधक इस सुधार करेंगा।

बैक के खाताधारक राजु पाटीदार, संदिप पाटीदार, भोला कहार, मयुर जोशी का कहना है कि, कियोस्को बैंक में आये दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। पहले भी आठ दिन तक बैक का इनवेटर खराब हो गया था जिससे हमे काफी परेशानी हुई। बैक मैनेजर विमल पाटीदार ने इस सम्बंध में कहा कि, बाहर से सर्व डाउन को चेक करने इंजीनियर आये हैं चेक किया जा रहा है।

खाद्य पंजीयन व अनुज्ञप्ति शिविर आयोजित

माही की गूंज, जामली।

खाद्य व्यवसाय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के द्वारा खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) बनाने हेतु एक दिन का शिविर लगाया गया। जिसके तहत सब्जी-फल विक्रेता, मांस विक्रेता, मछली अंडा विक्रेता, पान गुमटी, पानी पुरी चाट सेंटर, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान, समस्त किराना दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, स्वयं सहायता समूह, शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में संचालित कैंटीन, आइसक्रीम पार्लर, बेकरी, मेडिकल दुकान, दूध विक्रेता (फेरी, डेयरी), आटा चक्की इत्यादि को खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) लेना अनिवार्य है। बिना खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) व्यवसाय संचालन पाए जाने पर जुर्माने का प्रावधान है।

जिसके लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन झाबुआ के द्वारा ग्राम जामली में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे जिला खाद्य अधिकारी राहुल सिंह अलावा की मौजूद में कई पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्राप्त किए। वही अधिकारी अलावा द्वारा बताया गया कि, अगर कोई व्यक्ति का लाइसेंस (पंजीयन) नही बन पाया हो वो अपने निकटतम एमपी आनलाईन सेन्टर पर जाकर बनवा सकता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्चुअली हितग्राहियों को किया लाभान्वित

माही की गूंज, थांदला।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंगलवार हंसध्वनि सभागृह, रवीन्द्र भवन, भोपाल से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को वर्चुअली हितलाभ वितरण आयोजन किया गया। जिसमे 70 हज़ार हितग्राहियों का गृह प्रवेश एवं 30 हज़ार से अधिक हितग्राहियों को राशि 300 सौ करोड़ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की गई। जिसके तारतम्य में थांदला नगर में भी नवीन बने भवनों का ग्रह प्रवेश एवं हितग्राहियों को द्वितीय किस्त राशि का वितरण 1 क्लिक के माध्यम किया गया। उक्त आयोजन में नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी पणदा, पार्षद एवं मंडल अध्यक्ष समर्थ उपाध्याय, मंडल महामंत्री सुनील पणदा, सहकार भारती जिला महामंत्री दिलीप डामोर, संदीप डामोर निकाय कर्मचारीगण उपस्थित थे।

महाविद्यालय में किया आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का आयोजन

माही की गूंज, थांदला।

एक दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि खेमसिंह चौहान व विशिष्ट अतिथि अशरफ खान द्वारा आपदा को कैसे प्रबंध करें यह बताया गया, कैसे अपने परिवार, स्वजनों एवं मित्रों की सुरक्षा के उपाय बताए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य डॉ जीसी मेहता ने कहा कि, कुछ आपदा प्राकृतिक होती है एवं कुछ आपदा सार्वजनिक होती है। कार्यक्रम में डॉक्टर पीटर डोडिया सर ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि, नौगांवा नदी के छोटे पुल पर आपदा प्रबंधन नहीं होने के कारण पूर्व में एक अभियंता की जान चली गई। इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह मुवेल एवं आरक्षक राहुल जमरा, रमेश डामोर, विकास भुरिया, प्रताप कटारा तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक अजय भाबोर ने किया। आभार राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉ छगन वसुनिया ने माना।

लक्ष्मी नारायण मंदिर पर श्री भागवत कथा का समापन चल समारोह निकला

जब-जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान अवतार लेकर पापियों का नास करते हैं: पंडित केशव चतुर्वेदी

माही की गूंज, सारंगी।

माता-पिता और गुरु को नमन करने वाला सौभाग्यशाली होता है, किंतु हम पढ़-लिख गए हैं तो उनके सामने झुकने में शर्म आती है जिन्हे अपने माता-पिता और गुरु का आशीर्वाद मिला वह धन्य हुए है। कोई पुराण नहीं कहता कि, बच्चों को सजा दो, बल्कि उन्हें सीख दो। संस्कारी हमारे व्यक्तित्व का आधार है क्योंकि संस्कारों के बिना शिक्षा अधूरी है। यही भावी पीढ़ी हमारे जीवन में उद्धार करेगी। माता यशोदा ने भगवान कृष्ण की बाल लीला में माखन चुराने पर उन्हें मातृत्व प्रेम से उन्हें सिखाने का प्रयास किया और प्रेम की डोरी से मां यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांधा था, यह बात लक्ष्मी नारायण मंदिर पर चल रही। सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समापन दिवस पर कथा का वाचन करते हुए भागवताचार्य पंडित श्री केशव चतुर्वेदी ने कही।

पंडित जी ने अपने कथा मैं कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध एवं भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी विवाह के प्रसंग को विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने बताया कि, राजा बलि पूर्व जन्म में एक डाकू थे किंतु अनायास ठोकर लगने पर फूल की पत्ती शिवजी पर चढ़ गई और मोक्ष की प्राप्ती हुई। वह अगले जन्म में राजा बलि हुए, थोड़ा सा पुण्य करो तो उसका फल प्राप्त होता है। पंडित जी ने कहा कि, जब-जब धर्म की हानि होती है और अधर्म को बढ़ावा मिलता है भगवान धरती पर जन्म लेकर पापियों का अंत करते हैं। कंस के अत्याचार से दुखी होकर जब भक्तों ने प्रभु को याद किया तो भक्तों के दुख दूर करने व माता देवकी और वसुदेव जी के मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर आए। गोवर्धन पूजा का प्रसंग सुनाते उन्होंने कहा कि, एक बार इंद्र को अभिमान हो गया इसी अभिमान को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज वासियों से गिरिराज महाराज की पूजा कराई। इंद्र ने घनघोर वर्षा की पर भगवान ने अपनी उंगली पर 7 दिन और 7 रात तक गिरिराज पर्वत धारण कर सभी ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र के अभिमान को चुर-चुर किया।

भागवत कथा के समापन दिवस पर समिति द्वारा पंडित जी का व्यास पीठ पर साल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भजन ''एक दिन भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी'' व ''द्वारकानाथ मारो राजा रणछोड़ छे'' पर झूम कर नाचे। पूरे ग्राव में भक्तों द्वारा भागवत पुराण एवं पंडित जी का ढोल-धमांकों के साथ चल समारोह निकाला गया।

8 अगस्त से संगीत मय शिव महापुराण कथा का आयोजन

माही की गूंज, थांदला।

श्रावण अधिक मास के महीने में पुरा नगर भक्ति मय हो गया। पुरुषोत्तम अधिक श्रावण मास में प्रत्येक मंदिरों व शिवालयो पर भक्तों का तांता लगा रहता है। प्रातः से ही मंदिरो में पूजा-अर्चना आरंभ हो जाती। नगर की महिला मंडली द्वारा सभी मंदिरों में शाम के समय बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा है। इस ही कड़ी में थांदला में संगीत मय शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा हैं।

आयोजन की जानकारी देते हुए सांवरिया सेठ मंदिर के पुजारी पंडित हिमांशु (बिट्टू) भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि, पुरुषोत्तम अधिक श्रावण मास में सांवरिया सेठ मंदिर पर गुजरात के प्रसिद्ध कथा वाचक आचार्य जैमिन शुक्ल द्वारा संगीत मय महाशिवपुराण का आयोजन 8 अगस्त से 16 अगस्त तक किया जा रहा हौं आयोजन के पहले दिन कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा बावड़ी मंदिर से आरंभ होकर नगर में भ्रमण कर कथा स्थल पर पहुंचेगी। कथा प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। 14 अगस्त को महाशिवरात्रि पर अभिषेक, यज्ञ, भस्म आरती का आयोजन किया जाएगा। 16 अगस्त को पुरषोत्तम मास के समापन के साथ शिव महापुराण की पूर्णाहुति होगी। आयोजन समिति ने सभी भक्तों को अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा श्रवण कर धर्म लाभ लेने का आग्रह किया है।

संपादकीय

लापता हो गई लाखों महिलएं

इन आंकड़ों पर अविश्वास का कोई कारण नजर नहीं आता कि देश में दो साल के भीतर 13.13 लाख महिलाएं और लड़कियां लापता हुई। वजह यह कि आंकड़ा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने जुटाया है और संसद के पटल पर रखा गया है। वैसे इस बात की कोई गारंटी भी नहीं कि देश के दूर-दराज के इलाकों से लापता हर महिला और लड़की की गुमशुदगी भी इन आंकड़ों में शामिल हो। वैसे भी बहुत से लोग कथित इज्जत के नाम पर रिपोर्ट दर्ज कराने से गुरेज करते हैं। बहरहाल, यह किसी सभ्य समाज के माथे पर कलंक ही है कि महज दो साल में तेरह लाख से अधिक महिलाएं और लड़कियां गायब हो जाएं और उनकी कोई खैर-खबर न मिले। यह संकट जहां पुलिस-प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है, वहीं समाज को भी आत्ममंथन को बाध्य करता है कि हमने ऐसी स्थितियां क्यों बनने दी कि महिलाओं ने परेशान होकर घर छोड़ा या फिर वे असामाजिक तत्वों के चंगुल में फंस गईं। निस्संदेह, यह दुखद स्थिति है और लापता होने का आंकड़ा बहुत बड़ा है और चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यह विडंबना ही है कि मणिपुर मुद्दे पर जारी राजनीतिक कोलाहल के बीच इस ज्वलंत मुद्दे पर गंभीर राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं आई। दु:खद स्थिति यह भी है कि लापता होने वाली महिलाओं में ढाई लाख की संख्या नाबालिग लड़कियों की है। कहना मुश्किल है कि वे मानव तस्करी करने वालों के हत्थे चढ़ीं या अपने किसी परिचित के साथ नये जीवन की शुरुआत के लिये निकलीं। यह कहना भी कठिन है कि 2021 के बाद स्थितियां बदल गईं और इन आंकड़ों में कुछ लाख और महिलाएं व लड़कियां शामिल नहीं होंगी। लेकिन कुल मिलाकर हमारे समाज में स्थितियां ऐसी नहीं हैं कि एक आम महिला आत्मसम्मान व सुरक्षा का जीवन सहजता से जी सके। जिसको लेकर गंभीर मंथन करने की जरूरत है।

बहरहाल, तेरह लाख महिलाओं व लड़कियों का लापता होना समाज में विमर्श की मांग करता है कि आखिर वे गई कहां। निश्चित रूप से हालिया वर्षों में समाज में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में खासी तेजी आई है। निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिये जो सख्त कानून बने भी, उनका अपेक्षित प्रभाव समाज में नजर नहीं आता। आये दिन समाज में महिलाओं के अपहरण, बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा मानव तस्करी के समाचार अखबारों की सुर्खियां बनते रहते हैं। ऐसे में हम इन महिलाओं के लापता होने के लिये सिर्फ सरकार को ही दोषी नहीं ठहरा सकते। पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि अपराधी व सिरफिरे आशिक एकतरफा प्यार में विफलता के बाद सार्वजनिक रूप से लड़कियों की हत्या करते रहे और भीड़ तमाशबीन बनी रही या वीडियो बनाने में मशगूल रही। ऐसे में महिलाओं व लड़कियों के लापता होने में समाज अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई क्रूरता ने देश को दुनिया में शर्मसार किया, जहां जातीय दुश्मनी के बदले का शिकार महिलाओं को बनाया गया। ऐसे में समाज के हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना होगा कि क्या हम ऐसा समाज बनाने में योगदान दे रहे हैं,जहां किसी भी महिला के लापता होने की स्थिति न बने। कन्या भ्रूणहत्या करने वाले तथा दहेज के लिये विवाहिता को मारने वाले भी इसी समाज का हिस्सा हैं, जो महिलाओं के प्रति क्रूरता का ही एक रूप है। देश के कई भागों में असंतुलित लिंग अनुपात भी स्त्री विरोधी सोच की बानगी है। यह सोच महज सख्त कानून से नहीं बदलने वाली। हमें सोचना होगा कि महिलाएं क्यों यौन हिंसा की शिकार बन रही हैं? क्यों समाज में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, अपहरण व दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं? जाहिरा तौर पर ये समाज में पनप रही विषाक्त सोच की ही परिणति है। यह तय है कि किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति उसके सभ्य या असभ्य होने का परिचायक है। हमें अपने गिरेबां में झांकना होगा कि हम इस कसौटी पर कहां खड़े हैं? जिसके लिये समाज और राजनीतिक नेतृत्व को गंभीर पहल करनी होगी।

कर्ज वसूली नीति में विसंगति के यक्ष प्रश्न

देविंदर शर्मा

कुछेक साल पहले की बात है, हरियाणा का एक किसान भूमिगत पाइप के लिए उधार लिए गए छह लाख रुपये नहीं चुका सका। इस पर स्थानीय अदालत ने उसे दो साल के लिए जेल भेज दिया। इसके अलावा उस पर अतिरिक्त 9.83 लाख रुपये जुर्माना भी लगा दिया गया। केवल हरियाणा में ही नहीं, बल्कि हाल के सालों में देशभर में ऐसे सैकड़ों किसान पैसा न चुका पाने के चलते सलाखों के पीछे पहुंचाए गये, जिनकी ओर बैंकों की मामूली राशि ही बकाया थी। यदि जेल भी न भेजे गये, तो ऐसे किसानों की बड़ी संख्या है जिनकी जमीन कुर्क करने से पूर्व बैंक उनके ट्रैक्टर व अन्य अचल संपदा को जब्त करते रहे हैं।

आमतौर पर फसल नष्ट होने या फिर रेट गिर जाने की वजह से किस्तों का भुगतान न कर सकने वाले इन छोटी अवधि के बकायेदारों के बचाव में आने के बजाय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी, धोखा करने वाले और जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले अमीरों को रक्षा कवच प्रदान किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार कर आरबीआई ने जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए समझौता निपटान या तकनीकी बट्टे खाते में डालने की अनुमति राष्ट्रीयकृत बैंकों को दी है। बारह महीने की 'कूलिंग अवधि' के बाद, ये डिफॉल्टर, जिनके पास भुगतान करने की क्षमता है लेकिन पैसा लौटाने से इनकार करते हैं, नये लोन प्राप्त कर सकते हैं।

जैसा कि आरबीआई कहता है, यदि यह समाधान का एक वैध तंत्र है तो पहले इसी प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये कि क्यों किसी विरले मामले में ही यह समाधान एमएसएमई सेक्टर और किसानों पर लागू होता है, या फिर उस मध्यम वर्ग पर भी कभी-कभार ही क्यों लागू हुआ हो जो टैक्स देने के बाद बची अपनी मेहनत की कमाई से कार लोन या गृह ऋण लेते हैं। इसके अलावा कोई कारण नहीं बनता कि क्यों बैंकों, नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनांस संस्थाओं द्वारा रखे गये भाड़े के लोग कर्ज चुकाने में असमर्थ लोगों की अचल संपत्तियां जब्त करने के लिए नियमित तौर पर कड़े और अशिष्ट हथकंडे अपनाते हैं। हाल ही के एक मामले में एक ऋण डिफाल्टर से रिकवरी एजेंटों द्वारा टोल बैरियर पर ही कार जब्त कर ली गयी। इसी तरह एक अन्य मामले में झारखंड में कर्ज न चुका पाने वाले एक किसान की गर्भवती बेटी की मौत के लिए एक नॉन बैंक वित्तीय कंपनी के प्रमुख ने क्षमा मांगी है। उस लड़की को रिकवरी एजेंटों ने उस वक्त कुचल डाला था जब वे उसके किसान पिता का लोन पर लिया गया ट्रैक्टर लेकर भागने का प्रयास कर रहे थे। आरबीआई ने इस ओर से नजरें फेर ली थीं।

असल में सबसे पहले तो आरबीआई के उस विवादास्पद सर्कुलर से बेहद हैरान हूं, जिसने बैंकों को जानबूझकर ऐसे डिफाल्टर्स के साथ समझौता निपटान करने की अनुमति दी, जिन्हें वास्तव में अब तक जेल में होना चाहिए था। दूसरे, इस सर्कुलर के बारे में मुद्दा उछलने के बाद जारी किए गए सतही स्पष्टीकरण से जवाब मिलने के बजाय और अधिक सवाल खड़े हो गए हैं। यह यही दर्शाता है कि आरबीआई की उदारता केवल अमीर डिफॉल्टरों के लिए है, जो यूं भी बैंकिंग नियामक द्वारा तय नियमों-विनियमों की कोई खास परवाह नहीं करते हैं। अन्यथा कैसे और क्यों जानबूझकर डिफाल्टरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो बीते दो सालों में 41 फीसदी तक बढ़ चुकी है।

जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़कर 16,044 हो गई है- जिन पर बैंकों का सामूहिक रूप से 3.46 लाख करोड़ रुपये बकाया है। इसके अलावा, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पिछले सात वर्षों में बैंक धोखाधड़ी और घोटालों में हर दिन 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। कई जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले जिनमें विजय माल्या, मेहुल चोकसी और ललित मोदी जैसे लोग शामिल हैं, जो देश छोड़ भाग गए, को अब बैंकों के साथ समझौते के तहत राहत मिलेगी, उनमें कई भारी राइट-ऑफ (कर्ज बट्टे खाते) प्राप्त करने और फिर भी नए ऋण मांगने के लिए योग्य होंगे।

हैरानी है कि आरबीआई की ओर से ऐसी दरियादिली कभी छोटी राशि के ऋण डिफाल्टरों के प्रति क्यों नहीं दिखाई गयी जिनमें किसान भी शामिल हैं। छोटे किसानों को जेल की सजा क्यों भुगतनी पड़ती है, जबकि अमीर धोखेबाज व्यवसायियों को नियमित जमानत मिलती है, भारी कटौती होती है और उनका शानो-शौकत की जिंदगी चलती रहती है।

कई बार मैं सोचता हूं कि बैंकिंग सिस्टम अपने आप में ही बढ़ती असमानता का प्राथमिक कारण है। आखिरकार, यदि बैंकिंग सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाले कर्जदारों के साथ बैंक नाजुकपन से पेश आयेंगे तो यह उसी गेम प्लान को उजागर करता है जो अमीर वर्ग को धन बटोरने में मददगार बनती है। बैंक उन्हें जनता के पैसे से छूट देकर उबारना जारी रखते हैं। पहले ही, बीते दस सालों में 13 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का एनपीए बट्टे खाते डाल चुके हैं और जानबूझकर डिफाल्टर्स के लिए समझौता फार्मूला तैयार करने की बैंकों को दी गयी विवेकाधीन शक्ति ऐसे अमीरों के लिए सोने में सुहागा जैसा काम करेगी।

हालांकि अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ आरबीआई की नीति के आलोचक रहे हैं,वहीं अधिकांश व्यावसायिक मीडिया इसका समर्थक रहा है। इससे भी अधिक रोचक यह कि जब भी कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने वाला कोई मुद्दा सामने आता है, कितना भी गलत निर्णय क्यों न हो, कहीं से भी कार्पोरेट अर्थशास्त्रियों का समूह उसका बचाव करने की कोशिश करता नजर जाता है। यह तब हुआ जब ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने घोर असमानताएं कम करने के लिए संपत्ति कर लगाने के लिए कहा। भारत में कुछ अर्थशास्त्रियों ने तब कहा था कि अमीरों के एक छोटे से वर्ग से संपत्ति कर उगाहना किफायती नहीं होगा। हैरानीजनक है कि कैसे कुछ अर्थशास्त्री, आरबीआई के निर्देश को सही ठहराने की कोशिश करते हुए, यहां तक कह देते हैं कि ऋण की वसूली करते समय, बैंक को कोई अंतर नहीं करना चाहिए कि कर्ज न चुकाने का काम जानबूझकर किया गया, या फिर किसी अन्य तरीके से।

यदि ऐसा है तो मध्यम वर्ग के निवेशकों और किसानों के लिए इस छूट की इजाजत क्यों नहीं दी गयी। यदि किसान और मध्यम वर्ग के डिफाल्टर्स को भी यह लाभ मिलने लगे तो आप देखेंगे कि यही अर्थशास्त्री इस नीति पर सवाल उठा रहे होंगे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मीडिया में वे विशेषज्ञ और अन्य लोग जिन्होंने कर्नाटक में रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा पर सवाल उठाया था लेकिन जब 3.46 लाख करोड़ रुपये के संभावित बट्टे खाते में डालने पर सवाल पूछा जाता है और वह भी जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले वर्ग के लिए तो वही लोग चुप्पी साध लेते हैं। उन्हें इस उदारता से कोई दिक्कत नहीं है।

उम्मीद की जानी चाहिए कि आरबीआई कम से कम गरीब लाभार्थियों के प्रति निहित पूर्वाग्रह से परहेज करेगा। इसके विपरीत, बैंकिंग व्यवस्था के चालबाजों व धोखेबाजों के लिए जीवनदायी लाभ प्रदान करने वाला विवादास्पद सर्कुलर साफ तौर पर दर्शाता है कि आरबीआई को बहुत कुछ सीखना है, और शायद उस 'दोहरे मानक' को रोकने के लिए एक ठोस प्रयास करना है जो सभी तरह के आर्थिक लाभ प्रदान करने को लेकर अमीरों का पक्ष लेता है और कथित राष्ट्रीय बैलेंस शीट बिगाड़ने और नैतिक ख़तरा बनने के लिए गरीबों की निंदा करता है।

बिना चर्चा सदन से पारित कानून अवैध?

सनत कुमार जैन

पछले कई सत्रों मे लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभाओं में बिना चर्चा के बिल पास किए जा रहे हैं। वह कानून बन रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो कानून बनाती हैं। उसका असर नागरिकों पर पड़ता है। नागरिक अधिकार के तहत मतदाता, मतदान के माध्यम से अपने लिए विधायक और सांसद चुनते हैं। चुनाव के बाद यह माना जाता है, कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने विधानसभा क्षेत्र /लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जन भावनाओं को समझते हुए, संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही अथवा जो कानून बनाए जाते हैं, वह सदन के अंदर अपनी राय रखते हैं,विचार विमर्श होता है। बहुमत के आधार पर संसद और विधानसभाओं में कानून बनेंगे, जो लोगों के हितों का संवर्धन करने वाले होंगे। पिछले कुछ सत्रों से यह देखा जा रहा है कि संसद और विधानसभाओं की बैठकें बहुत कम हो रही हैं। सरकार और विपक्ष के बीच में सदन की कार्यवाही को लेकर मतभेद होता है। सरकार चाहती है, कि उसे सदन के अंदर जवाब ना देना पड़े। सरकार,विपक्ष का सामना करने से बचती है। पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों कानून बिना किसी चर्चा के लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभाओं से पारित किए गए हैं। बिना चर्चा के जो कानून पारित किए गए हैं। क्या उन्हें वैध माना जाना चाहिए। इसको लेकर अब बड़े पैमाने पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो भी विधेयक पिछले वर्षों में पेश किए गए हैं, उनमें लगभग-लगभग 90 फ़ीसदी से ज्यादा विधेयक संसदीय समिति को भी नहीं भेजे गए हैं। विधेयक संसद और विधानसभाओं में सीधे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। संसद अथवा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ घंटे पहले बिल एवं अन्य प्रस्ताव सांसदों और विधायकों के बीच में वितरित कर दिए जाते हैं। वह उनका अध्ययन भी नहीं कर पाते हैं। सरकार हो हल्ले और हंगामे के बीच सदन में प्रस्तुत करती है। आसंदी भी बिल पास करने की औपचारिकता को पूर्ण करा देता है। कुछ ही मिनटों में कई कानून पास कर दिए जाते हैं।

संविधान निर्माताओं ने आसंदी को जो शक्तियां दी हैं। उन शक्तियों का प्रयोग करने में आसंदी विफल साबित होती नजर आ रही है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, अथवा विधानसभा में आसंदी, के पद पर बहुमत के आधार पर सत्तारूढ़ पक्ष की मेहरबानी से पद धारण करते हैं। यही दबाव उनके ऊपर आसंदी पर बैठने के बाद भी बना रहता है। संविधान निर्माताओं ने यह माना था, कि अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो जाने के बाद, आसंदी दलगत राजनीति से अलग होगी। निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन होगा। सदन के अध्यक्ष सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों का संरक्षण करेंगे। चाहे वह सरकार हो, चाहे विपक्ष हो। सभी सांसदों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्र की बात कहने का सदन में अधिकार होगा। जो भी नियम, कानून सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। उन पर सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अधिकार होगा। सदन के अंदर निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके उठाए गए हर प्रश्न का जवाब सरकार से दिलाने की जिम्मेदारी आसंदी की ही होती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का संवैधानिक निजी अधिकार है, इसे बहुमत के आधार पर बाधित नहीं किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में स्थिति बिल्कुल उलट नजर आ रही है। चुनिंदा सांसदों अथवा विधायकों को एक या 2 मिनट में अपनी बात कहने का मौका सदन में दिया जा रहा है। सांसद और विधायक जो प्रश्न लगाते हैं। उनके उत्तर भी सरकार से नहीं मिलते है। तारांकित और अतारांकित प्रश्न लगाने में सचिवालय मनमाने तरीके से प्रश्न चयनित करते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के सामान्य अधिकार भी अब आसंदी के रहते हुए सदन में सुरक्षित नजर नहीं पा रहे हैं। पिछले एक दशक में लोकसभा, राज्यसभा एवं विधान सभाओं के सत्र अवधि कम होती जा रही है। पूरा सत्र हंगामे और हो-हल्ले मे खत्म हो जाता है। निर्धारित समय के पहले ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाती है। सदन में प्रस्तुत विधेयक, बजट अनुपूरक बजट विधि विधाई से संबंधित संशोधन हो -हल्ले के बीच ना और हां के जरिए मतदान कराकर आसंदी द्वारा स्वीकृत किए जा रहे हैं। सरकार जो चाहती है, वह आसंदी कर देती है। इसे संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। आसंदी की जिम्मेदारी है,कि वह सदन की कार्रवाई मे सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दे। आसंदी को अधिकार है, कि वह सरकार और विपक्ष के बीच में समन्वय बनाए। गतिरोध को दूर कराने में आसंदी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब दोनों पक्षों में विवाद शांत ना हो रहा हो। उस समय आसंदी निष्पक्षता के साथ पक्ष और विपक्ष के बीच आम सहमति बनाने का कार्य,हमेशा से करती आई थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आसंदी सरकार के दबाव में काम करती हुई स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। इसके कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार गतिरोध बढ़ रहा है। संसद और विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नियमों के अनुसार संचालित हो। इसका दायित्व आसंदी का होता है। आसंदी निष्पक्ष तरीके से काम करती है, तो वह सरकार और विपक्ष पर दबाव बनाती है। अब उल्टा हो रहा है। आसंदी कहती है, सदन की कार्यवाही चलाने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार के कामकाज को निपटाने के लिए ही सत्र बुलाया जाता है। आसंदी सरकार को संरक्षण देती है। जिसके कारण आसंदी के साथ, अब विपक्ष के रिश्ते बेहतर नहीं हैं। आसंदी जब सरकार का हिस्सा बन जाती है। इसका मतलब,आसंदी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर विपक्ष को विश्वास नहीं रहता। जो भी विधेयक सदन में बिना चर्चा पारित किए जा रहे हैं। वह एक तरह से अवैध माने जाने चाहिए। सदन में बिना चर्चा कराए, आसंदी ने बिना चर्चा के जो बिल पारित किए हैं। इसे अवैधानिक ही माना जाना चाहिए। संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना है। तो इस दिशा में सभी को सोचना होगा। न्यायालयों को भी यह देखना होगा कि जो कानून बनाए गए हैं वह विधिवत तरीके से पास हुए हैं या नहीं। यदि नहीं हुए हैं,तो उन कानून और नियमों को अवैध मानते हुए, न्यायालयों को अपना निर्णय देना चाहिए। यही समय की मांग है। संवैधानिक संस्थाएं धीरे-धीरे सरकार पर आश्रित होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति हमें राजतंत्र और तानाशाही की ओर ले जा रही है। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है।

अंतरिक्ष से सीधे पृथ्वी पर पहुंचेगी सौर ऊर्जा

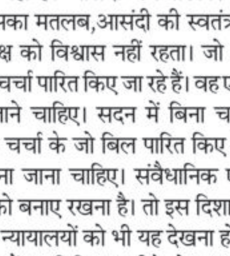

मुकुल व्यास

दुनिया में ऊर्जा के नए स्रोतों की तलाश करते हुए हमारा मुख्य फोकस सौर ऊर्जा पर है। लेकिन पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का अपेक्षित स्तर पर उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अंतरिक्ष से भी सौर ऊर्जा समुचित मात्रा में पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। अनुमान है कि सौर ऊर्जा का केवल 48 प्रतिशत ही पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है। ऊर्जा का शेष भाग पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों और धूल द्वारा अवशोषित किए जाने के कारण बाधित होता है। पृथ्वी का वायुमंडल भी सूर्य की 23 प्रतिशत किरणों को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देता है। इसलिए पृथ्वी पर इसका उपयोग करने के प्रयासों में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद हो रही है। सौर ऊर्जा को हासिल करने का सबसे टिकाऊ तरीका अंतरिक्ष से सीधे पृथ्वी को बिजली संप्रेषित करने का है।

दरअसल, सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर भेजने की पूरी प्रक्रिया बेहद महंगी है। इसके बावजूद यह सूर्य की अनंत ऊर्जा तक हमारी सीधी पहुंच को सुनिश्चित करती है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि अंतरिक्ष का वातावरण पृथ्वी की तरह सौर विकिरण को अवशोषित नहीं करता या बिखेरता नहीं है। इससे फोटोवोल्टिक सेलों को बादलों द्वारा बाधित हुए बिना अंतरिक्ष में अधिक ऊर्जा एकत्र करने का अवसर मिलता है। अंतरिक्ष आधारित ऊर्जा का दूसरा लाभ यह है कि ऊर्जा का उपयोग दिन के 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन किया जा सकता है। रात से बचने के लिए सौर ऊर्जा उपग्रहों को उचित कक्षा में स्थापित करके इसे पूरा किया जा सकता है। अंतरिक्ष-आधारित सौर ऊर्जा को व्यावहारिक बनाने के रास्ते में कई इंजीनियरिंग चुनौतियां हैं जैसे अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर सौर पैनलों के बुनियादी ढांचे को तैनात करना, जो एक कठिन कार्य है। इसके साथ ही लंबे समय तक सौर ऊर्जा का उचित उपयोग करने के लिए इसके संचालन को बनाए रखने की चुनौती भी आती है।

सौर ऊर्जा सबसे तेजी से विकसित हो रही अक्षय ऊर्जा है। इस समय वैश्विक बिजली उत्पादन में 3.6 प्रतिशत हिस्सा सौर ऊर्जा का है। इस तरह यह नवीकरणीय ऊर्जा बाजार का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद जलविद्युत और पवन ऊर्जा का स्थान आता है। आने वाले दशकों में इन तीन विधियों के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इनसे विद्युत उत्पादन 2035 तक 40 प्रतिशत और 2050 तक 45 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। हालांकि ऊर्जा क्षेत्र में इस परिवर्तन के लिए कई तकनीकी चुनौतियों और मुद्दों से निपटने की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उसकी अनियमितता है। पर्याप्त धूप उपलब्ध होने पर ही ऊर्जा एकत्र की जा सकती है।

इस समस्या का समाधान खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष-आधारित सौर ऊर्जा पर शोध करने में कई दशक बिताए हैं। वे पृथ्वी की कक्षा में ऐसे उपग्रह स्थापित करना चाहते हैं जो दिन में 24 घंटे और साल में 365 दिन बिना किसी रुकावट के ऊर्जा एकत्र करेंगे। इस प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैल्टेक) में स्पेस सोलर पावर प्रोजेक्ट (एसएसपीपी) के शोधकर्ताओं ने हाल ही में अंतरिक्ष से पृथ्वी तक पहला सफल वायरलेस पावर ट्रांसफर पूरा किया। यह पावर ट्रांसफर मैपल के जरिए किया गया।

मैपल दरअसल पृथ्वी की निम्न कक्षा से ऊर्जा हस्तांतरण के लिए बनाया गया एक प्रायोगिक प्लेटफॉर्म है जिसमें माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। मैपल का विकास अली हाजिमिरी के नेतृत्व में कैल्टेक की टीम ने किया है। मैपल प्लेटफ़ॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स द्वारा नियंत्रित लचीले और हल्के माइक्रोवेव ट्रांसमीटरों की एक सारणी होती है। इस तकनीक प्रदर्शक अथवा डेमोंस्ट्रेटर को कम लागत वाली सिलिकॉन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बनाया गया। इसे सौर ऊर्जा को एकत्र करके उसे दुनियाभर के स्टेशनों पर भेजने के लिए डिजाइन किया गया है।

अंतरिक्ष सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत 2011 में हुई थी। इस परियोजना के पहले डेमोंस्ट्रेटर को इस साल 3 जनवरी को एक स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लांच किया गया था। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा तभी व्यावहारिक हो सकती है जब इसके लिए प्रयुक्त उपग्रह हल्के और लचीले हों और ऐसे उपग्रहों को कम लागत पर प्रक्षेपित किया जाए। हल्के ढांचे का उपयोग करके अंतरिक्ष से वायरलेस पावर ट्रांसफर का सफल प्रदर्शन अंतरिक्ष सौर ऊर्जा की व्यावहारिकता और विश्व स्तर पर इसकी व्यापक पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बिजली देने के लिए अंतरिक्ष में पहले से ही सौर पैनल का उपयोग किया जाता है, लेकिन पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करने के लिए माइक्रोवेव ट्रांसमीटरों को तैनात करने के लिए अंतरिक्ष सौर ऊर्जा परियोजना को ऐसी ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों को विकसित करना पड़ेगा जो बहुत हल्की, सस्ती और लचीली हों। अंतरिक्ष सौर ऊर्जा परियोजना की प्रत्येक इकाई का वजन लगभग 50 किलोग्राम है। इसकी तुलना में छोटे उपग्रहों का वजन आमतौर पर 10 से 100 किलोग्राम के बीच होता है। प्रत्येक इकाई एक पैकेज में मोड़ी जा सकती है जो बाद में एक समतल वर्ग में फैल जाती है, जिसमें एक तरफ सौर सेल और दूसरी तरफ वायरलेस पावर ट्रांसमीटर होते हैं। यह प्रयोग यह दर्शाने में कामयाब रहा कि अंतरिक्ष में छोड़े जाने के बाद पावर ट्रांसमीटर ठीकठाक काम करते रहेंगे।

अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा को पृथ्वी तक भेजने के लिए एयरबस ने भी सितंबर, 2022 में एक प्रयोग किया था। यह एक छोटे पैमाने का प्रयोग था लेकिन यह बताने में काफी सफल रहा कि यह तकनीक स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य हो सकती है। यह प्रयोग जर्मनी में एयरबस की एक्स-वर्क्स इनोवेशन फैक्टरी में हुआ। इस प्रयोग में वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम 118 फीट की दूरी तक स्वच्छ ऊर्जा संप्रेषित करने में कामयाब रहा। संप्रेषित ऊर्जा का उपयोग हाइड्रोजन जनरेटर और फ्रिज को बिजली देने के साथ-साथ एक मॉडल शहर को रोशन करने के लिए किया गया था। टीम के इंजीनियरों को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इसका विस्तार किया जाएगा और लंबी दूरी तक इसका परीक्षण किया जाएगा। प्रयोग के सफल रहने पर अंततः अंतरिक्ष से ऊर्जा सीधे पृथ्वी पर संप्रेषित की जा सकेगी।

गांधीसागर अभ्यारण्य में लाए जाएंगे 10 नए चीते, जल्द शुरू होगी चिता सफारी

मन्दसौर। साहिल अगवान

देश में मध्य प्रदेश चीतों का स्थाई घर बनने वाला है। कूनो नेशनल पार्क के बाद अब मंदसौर जिले का गांधी सागर वन्य प्राणी अभयारण्य बनने जा रहा है। ?यहां दिसंबर तक दक्षिण अफ्रीका से 10 चीते आने वाले हैं। चीतों की नई खेप को अब कूनो नहीं ले जाएंगे। गांधी सागर बांध में चीतों के लिए तार फेंसिंग लगाने का तेजी से काम चल रहा है। चीता प्रोजेक्ट के तहत मप्र में अब कूनो में चीतों को नहीं भेजा जाएगा। दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका से 10 चीतों को लाया जाना है, लेकिन यह चीते अब कूनो के बजाय सीधे मंदसौर-नीमच जिले के गांधी सागर वन्य प्राणी अभयारण्य में भेजा जाएगा। यहां कई महीनो से जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और वन विभाग के सूत्रों के अनुसार करीब 17 करोड़ रुपए से तार फेंसिंग लगाने और बाड़ा तैयार करने का काम चल रहा है। लगभग ऐसी ही फेंसिंग का प्रोजेक्ट सागर के नौरादेही अभयारण्य में भी चल रहा है, हालांकि यहां पहले दौर में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत 15 टाइगर मौजूद हैं, इस कारण इसे चीतों के लिए ऑप्शन के तौर पर रखा गया है।

कूनो से पहले चीता सफारी भी शुरू हो सकेगी

कूनो नेशनल पार्क में चीतों को आए 10 महीने पूरे हो चुके हैं। 16-17 सितंबर 2023 को एक साल पूरा हो जाएगा। यहां चीता सफारी प्रारंभ होना फिलहाल तक संभव नजर नहीं आ रहा है। जबकि गांधी सागर अभयारण्य में चीता सफारी कूनो से पहले प्रारंभ करने की तैयारी है। सबसे अच्छी बात है कि गांधी सागर वन्य प्राणी अभयारण्य में चीतल सहित हिरण प्रजाति के भरपूर शाकाहारी जानवर मौजूद हैं, इस कारण चीतों को भोजन की दिक्कत भी नहीं होगी।

लव मैरिज की सजा: महिला को ससुराल से घसीटते हुए परिजन ले गए अपने गांव

मप्र मानव अधिकार आयोग ने एसपी से जांच कर तीन सप्ताह में मांगा जवाब

माही की गूंज, शुजालपुर।
अजय राज केवट माही

बेटी की लव मैरिज से नाराज परिजन ससुराल से घसीटते हुए गांव के चैराहे तक ले गये। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने एसपी, शाजापुर से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। मप्र मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने मामले में संज्ञान लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है।

शाजापुर जिले के शुजालपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम भीलखेड़ी भूगोर में बेटी के प्रेम विवाह से नाराज पिता, भाई एंव चाचा सहित अन्य लोगों ने हथियारों से हमला कर बेटी को ससुराल से घसीटते हुये गांव के चैराहे तक ले जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पचोर निवासी शिवानी विश्वकर्मा भोपाल के एक निजी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की नौकरी करती थी। सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी दोस्ती शुजालपुर के समीप भीलखेड़ी भूगोर निवासी सतीश विश्वकर्मा से हुई थी। परिवार की मर्जी के खिलाफ शिवानी बीते 13 दिसम्बर 2022 को शादी कर ली थी। इससे नाराज होकर शिवानी के परिजनों ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की, जिस कारण उसकी आखं एवं हाथ-पैरों गंभीर चोटें आई। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने एसपी शाजापुर से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के संबंध में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

जानिए पूरा मामला

जानकारी के अनुसार राजगढ़ जिले के पचोर निवासी शिवानी भोपाल के एक निजी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ में काम करती है। यहीं उसकी पहचान शुजालपुर के समीप ग्राम भीलखेड़ी (भूगोर) निवासी सतीश विश्वकर्मा से हुई। लड़की के परिजन उसका विवाह सतीश से करने के लिए सहमत नहीं थे। परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर शिवानी ने सतीश विश्वकर्मा से 13 दिसंबर 2022 को भोपाल के आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया और शादी के बाद से दोनों भोपाल ही रह रहे थे। हाल ही में एक माह पहले शिवानी अपने ससुराल ग्राम भीलखेड़ी में आकर रहने लगी थी, पुलिस थाना शुजालपुर मंडी में लड़की ने अपने माता-पिता और परिजनों से खतरा बताते हुए घटना का अंदेशा जताकर आवेदन भी दिया हुआ था।

उसके बावजूद गुरुवार की दोपहर 1:30 बजे जब वह अपनी सास कैलाश बाई व जेठानी दुर्गाबाई के साथ घर पर काम कर रही थी, तभी अचानक लड़की के मायके पक्ष के लोग हथियारों से लैस जीप में सवार होकर ग्राम भीलखेड़ी शिवानी के ससुराल पहुंचे और लड़की के पिता राधेश्याम विश्वकर्मा, ताऊ घनश्याम विश्वकर्मा, चाचा लखन विश्वकर्मा, उनके साथी प्रेम विश्वकर्मा, भाई शिवम और सुमित ने घर में घुसकर शिवानी की सास व जेठानी के साथ मारपीट की। इसके बाद सभी आरोपी शिवानी पर टूट पड़े। उसे मारपीट कर घायल कर दिया। शिवानी की आंख में गंभीर चोट आई है, मारपीट करते हुए शिवानी के पिता राधेश्याम, ताऊ घनश्याम, चाचा लखन और उनके साथी प्रेम ने हाथ पैर पकड़ कर उसे घसीटते हुए जबरन गांव के चौराहे तक ले आए। वह चीखती चिल्लाती रही, कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और पति के घर रहना चाहती है, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक नहीं सुनी।

भाई शिवम और सुमित ने भी शिवानी से मारपीट की गांव में अचानक हुआ हंगामा देख सरपंच मंगल सिंह राठौड़ सहित अन्य ग्रामीण वहां पहुंच और ग्रामीणों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी इस दौरान भी महिलाओं पर लकड़ियां फटकारते रहे। ग्रामीणों की भीड़ लगने व पुलिस के आने के बाद सभी लोग जीप में सवार होकर शुजालपुर की तरफ भागे, जिन्हे रास्ते में ही लोगों ने पकड़कर जीप में तोड़फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने तीन लोगों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया और अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जीप पुलिस थाने में खड़ी है, तथा उसमें से एक चाकू भी मिला है।

बस परमिट और समय को लेकर एजेंट और मालिक के बीच चले लाठी-डंडे, दो घायल

माही की गूंज, शाजापुर।

जिला मुख्यालय पर स्थित बस स्टैंड क्षेत्र में बस संचालक और बस एजेंट के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इसमें दो लोग घायल हो गए हैं। जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में किया गया। जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस बस स्टैंड पहुंची और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। शाजापुर प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से संचालित हो रही बसों की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी बिना परमिट और बिना फिटनेस की बसें सड़कों पर बेखौफ दौड़ती दिखाई देती है। जिसको लेकर प्रशासन ने बस एजेंट को इसका जिम्मा सौंपा और उन्हें कहा कि बिना परमिट की बसों को बस स्टैंड से बाहर न जाने दें, तभी एक बस का परमिट खत्म हो जाने पर उसे बस एजेंट द्वारा रोका गया। रोकने पर बस संचालक द्वारा एजेंट के ऊपर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया।

वहीं, बीच-बचाव करने आए बस एजेंटों द्वारा बस संचालक के खिलाफ धावा बोल दिया। जिसमें एक व्यक्ति बस का भी घायल हो गया। बस स्टैंड पर खूनी संघर्ष देख वहां मौजूदा लोगों में दहशत फैल गई और सभी यात्री डर गए। इसे देखते हुए पुलिस ने बस स्टैंड क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। सभी घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। फिलहाल शाजापुर कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है और मामले को जांच में लिया गया है।

नवागत एसपी ने राहुल कुमार लोधी ने संभाला पदभार

माही की गूंज, रतलाम।

कुछ समय पूर्व ही जिले की बाग डोर संभालने सभालने वाले एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा का भोपाल मुख्यालय स्थानांतरण हो गया है। सोमवार को गृह विभाग से जारी आदेश अनुसार एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा का स्थानांतरण भोपाल कर दिया गया है जहा पर वे सहायक पुलिस महानिरीक्षक का पद संभालेंगे। रतलाम एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा की जगह पर बुरहानपुर एसपी राहुल कुमार लोधा रतलाम के नए एसपी होंगे। अब तक रतलाम जिले में आये एसपी को अच्छा समय दिया गया, एसपी बहुगुणा ने भी आते हो अपराधीयो पर नकेल कसना शुरू की थी और नशे के अवैध व्यापार पर लगातार कार्यवाही की जा रही थी। ऐसे में अचानक उनका स्तान्तरण चौका देने वाला रहा और उनके स्तान्तरण को लेकर चर्चाएं है कि इसके पीछे कही न कही कोई राजनीतिक कारण रहे है। नए एसपी के रूप में एसपी राहुल कुमार लोधी ने पदभार ग्रहण किया। नये एसपी के सामने जिले नशे के फैलते कारोबार ओर बढ़ते अपराधों से निपटने की बड़ी चुनोती रहेगी।

महाभारत कालीन है पाण्डुखोर मंदिर, पांडवों ने यहां अज्ञातवास में की थी शिव की पूजा

माही की गूंज, शाजापुर। जिले में स्थित प्राचीन पाण्डुखोर (पांडू खो)का शिव मंदिर महाभारत कालीन है। मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहां गुफा में भगवान शिव की पूजा की थी। इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है।शाजापुर जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर इस गुफा में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कुछ दिन प्रवास किया था। इसी दौरान शिवलिंग की स्थापना भी की थी। इसके प्रमाण आज भी गुफा के रूप में विद्यमान इस मंदिर में नजर आते हैं।

पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर और शिवलिंग की बड़ी महिमा है। इसके चलते सावन महीने में प्रत्येक सावन को यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। लोग यहां भोले बाबा के सामने मनौतियां मांगने आते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने पर कांवड़ चढ़ाते हैं। इस मंदिर की प्राचीनता को लेकर यहां तरह तरह की कहानियां प्रचलन में हैं। शिवपुराण समेत कई अन्य पुराणों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है यह मंदिर पांडु खोरा के नाम से जाना जाता था।

महाभारत काल के दौरान यहां एक छोटी सी गुफा हुआ करती थी। जहां अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना की और उन्हें खुश करने के लिए पूजा की थी। घने पेड़ों के बीच स्थित मंदिर के के पास से एक नदी भी गुजर रही है जो मंदिर के सौंदर्य में चार चांद लगाती है। यहां दूर-दूर से लोग शिवजी से मन्नत मांगने के लिए आते हैं। भक्तों का मानना है कि, जो भी सच्चे मन से शिव जी के पास गुफा में बैठकर अपनी मनौती मांगता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

श्रद्धालुओं के मुताबिक पांडवों द्वारा स्थापित होने की वजह से ही इस मंदिर को पांडु खोरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। कोई भी भक्त कितने भी दुख में हो, यहां आते ही उसकी आधी बीमारी यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ही ठीक हो जाती है। बाकी भोलेनाथ की कृपा से वह कष्टमुक्त हो जाता है। इस मंदिर पर हर शिवरात्रि मेला लगता है। खासतौर पर सावन की शिवरात्रि पर तो लोग परिवार के साथ यहां आते हैं और भगवान शिव की पूजा के साथ ही अपने जरूरत की चीजों की खरीदारी करते हैं।

मंदिर के ठीक सामने ही एक बिल पेड़ भी है। जनश्रुतियों के मुताबिक यह पेड़ सदियों पुराना है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस पेड़ की उम्र की सही जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन मान्यता है कि यह हजारों साल से ऐसे ही है। इस मंदिर को भक्त भी अपनी सुविधा के मुताबिक अलग-अलग नाम से बोलते हैं। कोई इसे पांडुपुरा कहता है तो कोई पांडू खो। यहां तमाम पुरानी मूर्तियां भी हैं, लेकिन वह जीर्ण शीर्ण हालत में हैं।

स्कूटी प्रदाय पूर्व संचालन का दिया प्रशिक्षण

माही की गूंज, शाजापुर। छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को निःशुल्क ई-स्कूटी/आई-स्कूटी योजना का लाभ देने के लिए एक अगस्त को उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्रमांक 1 शाजापुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने विद्यार्थियों को योजना के लाभ एवं स्कूटी संचालन में यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी दी। कार्यक्रम में यातायात थाना प्रभारी श्री सत्येन्द्र राजपूत ने हेलमेट की अनिवार्यता पर मार्गदर्शन दिया। उल्लेखनीय है कि, कक्षा 12 वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त शिक्षा विभाग अंतर्गत हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के 126 छात्र-छात्राओं को म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क ई-स्कूटी/आई-स्कूटी प्रदाय की जायेगी। विद्यार्थी अपनी पसंद से स्कूटी का चयन करेंगे तो उन्हे अधिकतम 90 हजार रूपये आई.सी.ई. स्कूटी के लिए राशि उनके खातों में दी जायेगी और ई-स्कूटी चयन करने पर 1 लाख 20 हजार रूपये प्रदाय किये जायेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम में आईटीआई के ट्रेनिंग ऑफिसर अतुल पटेल, आरआर शर्मा, श्री अभय वर्मा, यातायात सहा. प्रभारी जितेन्द्र राजपूत, रवि वर्मा, गौरव व्यास आदि का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन हेमंत दुबे ने किया एवं आभार प्रदर्शन उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य प्रवीण मण्डलोई ने माना।

लूट की योजना बनाते चार आरोपी गिरफ्तार

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र की चंदवासा चौकी पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है वही इनका एक आरोपी मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार और वाहन चालकों को लूटने के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री बरामद की है। चंदवासा चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग मेलखेड़ा-चंदवासा रोड पर बुंदिया गांव के रास्ते पर बने यात्री प्रतीक्षालय के निकट बैठे हैं और लूट की कोई योजना बना रहे हैं।

मौके से संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर पूछताछ की जाए तो बड़ा खुलासा हो सकता है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम बनाकर मुखबिर के द्वारा बताए गए स्थान बुंदिया गांव के यात्री प्रतीक्षालय के निकट दबिश देकर आगर मालवा जिले के अर्जुन पिता गोपाल गुर्जर (20), महेश पिता देवीलाल मेघवाल (21), दिनेश पिता वरदा जी मेघवाल (45) और राहुल पिता मांगीलाल मेघवाल (22) को गिरफ्तार किया है, इनका एक साथी पंकज पिता गोपाल गुर्जर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 बोर का एक देशी कट्टा, 2 खटकेदार चाकू एक गुप्ति और किले लगी हुई लकड़ी का पटिया बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि जानकारी मिली थी कि, आरोपी सड़क पर किले लगी हुई लकड़ी का पटिया रखकर वाहन को पंचर कर राहगीरों को लूटने का प्रयास कर रहे थे। मामले में पुलिस ने आरोपियों खिलाफ लूट की साजिश रचने और अवैध हथियार रखने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया है।

शासकीय विज्ञापन बन गए भाजपा के पेम्पलेट, लाडली बहना की राशि 3000 होने का उल्लेख कहीं भी नही

3000 का झूठ शिव 'राज' की पराजय का संकेत, झूठा विज्ञापन बंद कर जिम्मेदारों पर दर्ज किया जाए प्रकरण

माही की गूंज, रतलाम।

शिवराज का लाडली बहना की राशि बढाकर 3 हजार रुपए प्रतिमाह करने का लॉलीपॉप जनता से धोखाधड़ी है। जबकि सरकारी दस्तावेजों में कहीं भी राशि 3000 रुपए करने का उल्लेख नहीं है। सरकारी विज्ञापन तो भाजपा के पेम्पलेट और अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता हो गये है। शिवराज द्वारा लगातार असत्य तथा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि लाडली बहना को प्रतिमाह मिल रहे पैसे एक हजार से बढकर तीन हजार हो जायगे। विज्ञापनो मे राशि प्राप्त करने वाली लाडली बहना की संख्या 1.25 करोड़ एवं अंतरित की गई राशि एक हजार 209 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जबकि विधानसभा में जीतू पटवारी के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि लाडली बहना की संख्या 1.12 करोड तथा उन को अंतरित की गई राशि एक हजार 117 करोड रुपए है।

फरवरी-मार्च 2023 के बजट में लाडली बहना के मद में 7 हजार 850 करोड़ रुपए तथा 12 जुलाई 2023 को अनुपूरक बजट में 2 हजार 800 करोड रुपए का प्रावधान किया गया तथा दोनो बजट मे वित्तमंत्री द्वारा प्रतिमाह एक हजार रुपए दिये जाने का उल्लेख किया गया। 11 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज ने विधानसभा में विधायक ब्रह्मा भलावी के प्रश्न के उत्तर में बताया कि, जून 2023 से मार्च 2024 तक लाडली बहना को लगभग 12096.44 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। जोकि 1000 रुपए प्रति माह के अनुसार है।

11 जुलाई 23 को विधानसभा में शिवराज द्वारा विधायक प्रवीण पाठक के प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि, सहायता राशि प्रतिमाह बढ़ाए जाने के संबंध में नीति निर्धारण प्रक्रिया प्रचलन में है। विधायक जयवर्धन सिंह के प्रश्न पर शिवराज ने यह उत्तर दिया कि, लाडली बहनों को दी जा रही राशि आगामी वर्षों में बढ़ाकर क्रमानुसार 1250 रुपए, 1500 रुपए, 1750 रुपए, 2000 रुपए, 2250 रुपए, 2500 रुपए, 2750 रुपए, 3000 रुपए तक करने एवं उपरोक्त क्रमानुसार वृद्धि हेतू राज्य मंत्री परिषद तथा विधानसभा से सक्षम स्वीकृति लेने और बजट प्रावधान करने कि निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नही है। लाडली बहना को प्रतिमाह रुपये 3000 दिए जाने की कोई नीति निर्धारित नहीं हुई है, राज्य मंत्रिपरिषद एवं विधानसभा की सक्षम स्वीकृति नहीं हुई है, कोई समय सीमा भी तय नहीं हुई है। इसके बावजूद यह झुठ परोसना, शिवराज की बुरी तरह हो रही पराजय का संकेत है।

कांग्रेस प्रदेश महासचिव, पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने बताया कि, मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि लाडली बहना के 3 हजार रुपए वाले विज्ञापनों पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा असत्य विज्ञापन किये जाने का खंडन प्रकाशित किया जाए। लाडली बहना के विज्ञापन के लिए भुगतान की गई राशि जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल की जाए और उन पर राज्य धन के दुरुपयोग का फौजदारी प्रकरण दर्ज हो।

प्लाट नही मिलने पर पीड़ित बालिका को कलेक्टर ने वापस दिलवाए 10 लाख रुपये

माही की गूंज, रतलाम।

त्वरित न्याय क्या होता यह देखने मंगलवार को रतलाम कलेक्टोरेट में आयोजित जनसुनवाई में देखने को मिला जहां, एक बालिका रत्नपुरी निवासी यशस्विनी महावर ने शिकायत में बताया कि उसने 2020 में 3200 स्क्वेयर फीट प्लाट खरीदा था, परंतु राजस्व निरीक्षक से अभी कुछ दिनों पूर्व सीमांकन कराया तो प्लाट मौके पर नहीं मिला। पीड़िता बालिका जनसुनवाई में आई, उसे सुनकर कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने फोरन तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को बरबड़ स्थित मौके पर भेजा। जिस व्यक्ति राजू तिवारी ने प्लाट बेचा था उसे भी बुलाया गया, पड़ताल में प्लाट नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने विक्रेता को निर्देश दिए कि बालिका को तत्काल राशि वापस करें।

कलेक्टर के निर्देश पर विक्रेता व्यक्ति घर से 10 लाख 64 हजार रूपए का चेक लेकर आया, बालिका को प्रदान किया। इस त्वरित न्याय से खुश बालिका यशस्विनी ने मुख्य मंत्री शिवराजसिंह चौहान के सुशासन को धन्यवाद दिया। साथ में मौजूद उसके भाई हर्षित ने भी धन्यवाद दिया।

गांधीनगर निवासी अजय कोटियाना ने बताया कि, विगत दिनों मोहल्ले में सीसी रोड का निर्माण किया गया है। पहले इस क्षेत्र में पानी की निकासी के लिए बडा पाईप लगाया गया था परन्तु ठेकेदार ने बडा पाईप निकालकर छोटा पाईप डाल दिए जाने से क्षेत्र में पानी भर जाने से घरों में पानी घुस जाता है जिससे नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। जिसके बाद अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए।

वार्ड 5 के रहवासियों द्वारा आवेदन देते हुए बताया कि विगत एक वर्ष से निगम के जल विभाग द्वारा जल प्रदाय नहीं किया जा रहा है। कई बार समस्या बताने पर केवल आश्वासन ही दिया जाता है। जिसके बाद आवेदन नगर निगम को समस्या निराकरण के निर्देश दिए। दीनदयाल नगर निवासी केसर गरवाल ने बताया कि, प्रार्थियां एवं प्रार्थिया का पति दोनों दिव्यांग होकर मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का लालन-पालन करते हैं तथा कच्चे मकान में रहते हैं। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि किराए का मकान ले सकें। जिसके बाद आवेदन निराकरण के लिए नगर निगम को भेज दिया गया है।

ग्राम रामपुरिया निवासी भमर पिता देवाजी ने आवेदन दिया कि, प्रार्थी की रीढ की हड्डी में बीमारी होने से प्रतिमाह पांच से सात हजार रुपए का खर्च आता है। प्रार्थी की स्थिति ऐसी नहीं है कि प्रतिमाह उक्त राशि की दवाई ले सके। आवेदन निराकरण के लिए सीएमएचओ को भेजा गया है।

सरपंच-सचिव ने फर्जी बिल लगाकर निकाली ली राशि, जनपद सीईओ को सौंपी गई जांच

माही की गूंज, खरगोन।

जनसुनवाई में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कई नागरिकों की समस्याओं को सुना। साथ ही कई प्रकरणों में जाँच करने तथा समय सीमा में निराकरण करने के अलावा उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को कॉल कर तथा व्हाटसअप करके भी समस्याओं के निराकरण कर निर्देश दिए है। जंप महेश्वर की ग्राम पंचायत बड़दि्या कि उपसरपंच श्रीमती संगीता बाई ने जनसुनवाई में कलेक्टर वर्मा को सरपंच व सचिव द्वारा फर्जी बिल लगाकर राशि निकालने की शिकायत की। कलेक्टर वर्मा ने तुरंत वीसी के माध्यम से जपं सीईओ आरिफ खान को जाँच करने के दिए आदेश। वहीं ग्राम कोठा खुर्द की ललिता मंडलोई ने शिक्षा विभाग में कार्यरत पति की मृत्यु होने के 4 वर्ष बाद अभी तक पेंशन न मिलने पर जनसुनवाई में दो बच्चों के साथ पेंशन चालू करवाने की शिकायत लेकर पहुंची। कलेक्टर वर्मा ने ललिता के पेंशन प्रकरण के आवेदन को टीएल बैठक के लिए मार्क किया हे। उन्होंने ललिता के प्रकरण को लेकर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक संचालक एबी गुप्ता को पेंशन स्वीकृत कराने के निर्देश दिए।

अवैध बिलों की जांच करेंगे जनपद सीईओ

इसी प्रकार कतरगांव ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव द्वारा अवैध तरीके से विधायक निधी से प्राप्त चबुतरा निर्माण की 1 लाख रूपये की राशि अवैध तरीके से निकालने व भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है। संतोष भालेकर ने जनसुनवाई में कलेक्टर वर्मा से कहा कि, सरपंच सचिव ने विधायक निधि से चबुतरा निर्माण की 1 लाख रूपये की राशि अवैध निकालकर नापेड में भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कचरा पेटी गांव से 2 किमी की दूरी पर बनाई है वह भी टूट गई है। साथ ही सरपंच सचिव ने गांव में स्ट्रीट लाईट के बिल लगे लेकिन अभी तक स्ट्रीट लाईट नहीं लगाई गई है। कलेक्टर वर्मा ने जनपद सीईओ को खुद ग्राम पंचायत जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं।

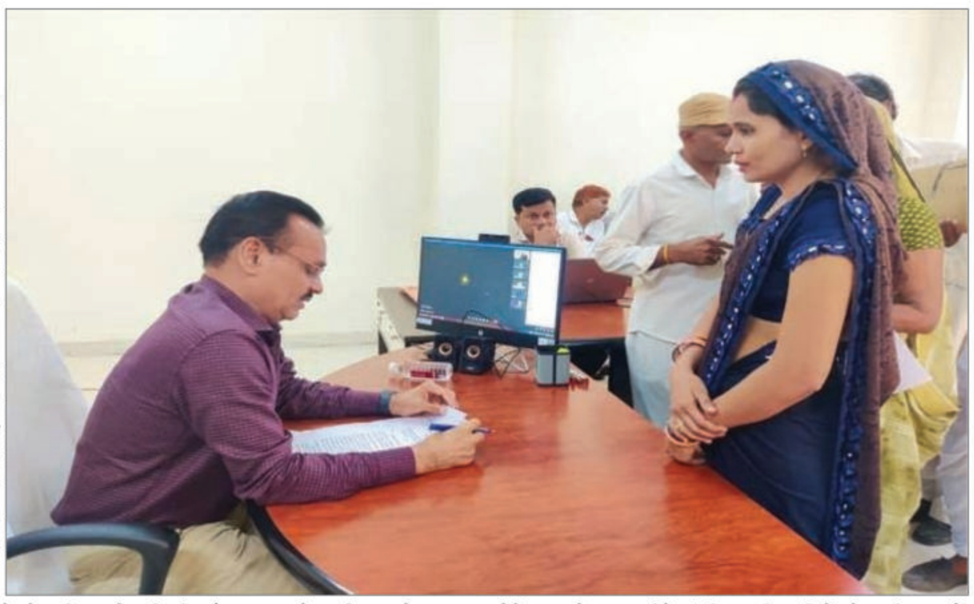

जल जीवन मिशन के कार्यों को अधूरा छोड़ने, राशि का भुगतान ने होने, बच्चों को दाखिला दिलाने, कच्चे रोड़ निर्माण के कारण खेत की फसले नुकसान होने संबंधी कई शिकायतों को जनसुवाई में सुना गया। कलेक्टर वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों के जांच कर निराकरण करने के लिए निर्देशित किया है।

स्वीप प्लान के तहत हर हाथ सशक्त लोकतंत्र का साथ थीम पर मानव श्रंखला का हुआ आयोजन

माही की गूंज, खरगोन।

जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं स्वीप प्लान के सहायक नोडल अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा निर्धारित तिथियों में मतदाता जागरूकता स्वीप प्लान अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत विकासखंड स्तरीय गतिविधियों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। नपा सीएमओ एमआर निगवाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका परिषद खरगोन द्वारा नगर पालिका कर्मचरीयों की उपस्थिति में मानव श्रंखला थीम पर ''हर हाथ सशक्त लोकतंत्र का साथ'' की थीम पर समस्त मतदाताओं को मतदान करने लिए शहर में स्थित रविन्द्रनाथ टैगौर पार्क में मानव श्रंखला कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। यहां मानव श्रृंखला के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया।

पूर्णतः जीरो वेस्ट इवेंट एवं होम कम्पोसि्ंटग बिन यूनिट वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

माही की गूंज, खरगोन।

नगर पालिका परिषद खरगोन द्वारा पीएम आवास योजना शहरी ने पूर्णत जीरो वेस्ट इवेंट एवं होम कम्पोसि्ंटग बिन यूनिट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पालिका खरगोन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि, पीएम आवास योजना अंतर्गत वर्तमान में शासन से कुल राशि 1 करोड़ 46 लाख रुपये प्राप्त होकर कुल 154 हितग्राहियों को विभिन्न स्तरों पर आवंटित की गई। प्रथम किश्त 7 हितग्राहियों को प्रति हितग्राही 1 लाख अनुसार कुल 7 लाख, द्वितीय किश्त 133 हितग्राहियों को प्रति हितग्राही 1 लाख अनुसार कुल 133 लाख, तृतीय किश्त 13 हितग्राहियों को प्रति हितग्राही 50 हजार अनुसार कुल 6.50 लाख वितरित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में होम कंपोस्ट खाद बनाने के लिए रहवासियों को होम कंपोस्ट बिन का वितरण किया गया। घर से निकलने वाले गीले कचरे से कंपोस्ट खाद बनाने के लिए खाद बनाने की विधि की जानकारी दी गई। विधि के माध्यम से घर पर खाद बनाकर छोटे-मोटे गार्डनिंग में खाद का उपयोग कर सकते हैं जिससे वार्ड में रहवासी आत्मनिर्भर बनेंगे। कार्यक्रम जीरो वेस्ट प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित किया गया जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक, ग्लास, चम्मच, प्लेट, कटोरी आदि पूरी तरह से वर्जित है। कार्यक्रम के दौरान पॉलिथीन, पन्नी, थर्माकोल से बनी सजावटी या अन्य सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती छाया जोशी, उपाध्यक्ष भोलू वर्मा, सांसद प्रतिनिधि राजेश रावत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एमआर निगवाल, स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते, एई श्रीमति पल्लवी पाल, उपयंत्री पूजा पटेल, स्वच्छता समिति सभापति श्रीमती पूजा जितेन्द्र चोपड़ा, भागीरथ कुमरावत समाजसेवी, दयालु पटवा जी, भागीरथ बडोले, महेश वर्मा, श्रीमति अनिता दिनेश पाटीदार, श्रीमति दुर्गा किशोर राठौड़ श्रीमती कविता अरविंद पाटीदार, समाज सेवी श्रीमति सुधा मोयदे, जगन्नाथ सावले एवं समस्त पार्षद गण, कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम संचालन राजकुमार शर्मा द्वारा किया गया।

लोकतंत्र में प्रत्येक वोट का महत्व होता है- प्राचार्य डॉ. वर्मा

माही की गूंज, बड़वानी।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अठारह वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रत्येक भारतीय को मताधिकार प्राप्त होता है। यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं दर्ज हुआ है, तो आप सबसे पहले मतदाता बनने की प्रक्रिया सम्पन्न कीजिए। यह प्रक्रिया बहुत सरल है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन यह कार्य सम्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 6 भरना होता है। आप अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करके भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बीएलओ स्वयं भी आपके घर पर आपसे संपर्क करते होकर हैं, तो उस अवसर का आप लाभ उठाइये। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे वोट डालने से या नहीं डालने से क्या फर्क पड़ता है। ऐसी सोच ठीक नहीं है। लोकतंत्र में प्रत्येक वोट का महत्व होता है। एक वोट से भी हार-जीत के उदाहरण मौजूद हैं। ये बातें स्वीप एक्टिविटी के अंतर्गत शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी के प्राचार्य डॉ. दिनेश वर्मा ने कॉलेज के युवाओं को संबोधित करते हुए कहीं। यह आयोजन कॉलेज के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब और स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के माध्यम से किया गया। कार्यकर्तागण प्रीति गुलवानिया और वर्षा मुजाल्दे ने बताया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के संदर्भ में इन दिनों स्वीप एक्टिविटीज का आयोजन किया जा रहा है। मतदान की दिलाई शपथ इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. वर्मा ने 1 अक्टूबर, 2023 तक अठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में नाम लिखवाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही जो पहले ही मतदाता बन चुके हैं, उनको शपथ दिलाई कि वे लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा के बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आयोजन में सहयोग सुभाष चौहान, जानकी बर्मन, अन्नपूर्णा कनेश, रूक्मणि अवास्या, मंजुला सोलंकी, विक्रम सेनानी, राधा सूर्यवंशी, पूनम कुशवाह और डॉ. मधुसूदन चौबे ने किया।

1 अक्टूबर 2005 से पूर्व जन्में युवा मतदाता सूची में जुड़वाए नाम

माही की गूंज, खरगोन।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुधवार से 1521 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य प्रारम्भ हो गया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी शिवराज सिंह वर्मा ने राजनीतिक दलों के साथ ईवीएम गोडाउन का मासिक निरीक्षण करने के बाद बैठक आयोजित की। बैठक में कहा कि 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व जन्में व्यक्ति पात्र है। 30 अगस्त तक चलने वाले इस कार्य में हर युवा का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाना है। राजनीतिक दल भी इसके लिए जल्द से बीएलए नियुक्त कर दें। जिला निर्वाचन अधिकारी वर्मा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वोटर हेल्पलाइन एप का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि इसे कैसे भी व्यक्ति प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड करने के बाद बारकोड, क्यूआर कोड, विवरण से तथा मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र से कैसे मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। साथ ही नए मतदाता कैसे एप के माध्यम से नाम जोड़ सकते हैं। जिसके सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं होगा। उसका सत्यापन का कार्य बीएलओ द्वारा किया जाएगा। साथ ही पता और नाम त्रुटिपूर्ण हो उसका भी संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरा जाएगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जेएस बघेल, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रताप सिंह अगास्या, एसडीएम भास्कर गाचले सहित जनप्रतिनिधियों में भाजपा के मोहन राठौड़, कांग्रेस के जितेन्द्र भावसार व सागर बेस, आम आदमी के सुरेश मोयदे सहित अन्य उपस्थित रहें।

कलेक्टर ने मतदाता जागरूकता रैली को दिखाई हरी झण्डी

माही की गूंज, बड़वानी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने बुधवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी से मतदाता जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी से प्रारंभ हुई इस मतदाता जागरूकता रैली में हजारो की संख्या में शामिल विद्यार्थियो ने ''सारे काम छोड दो, सबसे पहले वोट दो'' के नारे के साथ रैली बड़वानी शहर में निकाली गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे, उपजिला निर्वाचन अधिकारी सोहन कनाश, एसडीएम बड़वानी शक्तिसिंह चौहान, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग निलेशसिंह रघुवंशी, तहसीलदार बड़वानी जगदीश कुमार वर्मा, बीईओ पाटी श्रीमती राजश्री पंवार सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

कश्मीर में सेवा की अद्भुत मिसाल बने डॉ. अरविंद किराडे

माही की गूंज, बड़वानी।

विकासखंड पानसेमल के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरविंद किराडे अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिन-रात जुटे है। डॉ. किराड़े चंदनबाड़ी जम्मू कश्मीर मैं रहकर अमरनाथ यात्रियों के लिए सेवा भावना से कार्य कर रहे। पवित्र गुफा से लौटते समय 69 वर्षीय मध्यप्रदेश के डिंडोरी के रहने वाले नारायण टीकाराम राठौर को सांस लेने में तकलीफ हुई ।ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा तब मायोकार्डियल इनफेक्शन दिखाई दिया। तुरंत डॉ किराडे ने सीपीआर देते हुए उनकी जान बचाकर हायर सेंटर पर रवाना किया। डॉ. किराडे अमरनाथ यात्रियों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक मिसाल सिद्ध हो रहे हैं। पानसेमल विकासखंड के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ अरविंद किराडे अपनी सेवाओं के लिए क्षेत्र में भी जाने जाते हैं। वही अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू के चंदनबाड़ी में अपनी सेवाएं देकर स्वास्थ्य की दृष्टि से तकलीफ में फंसे यात्रियों की जान बचाने में अपना योगदान कर रहे हैं ।डॉ अरविंद किराडे के सेवा भाव को लेकर क्षेत्र के सभी लोगों ने प्रसंशा की है और इस अच्छे कार्य के लिए उन्होंने डॉ अरविंद किराडे को बधाई भी दी।

जिले में आवास का आंकड़ा एक लाख पार, प्रदेश में आठवीं व संभाग में मिली पहली रैंक

माही की गूंज, खरगोन।

जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में एक लाख आवास बनाने का आंकड़ा पार हो गया है। 31 जुलाई तक 101386 हितग्राहियों का ग्रह प्रवेश हो चुका है। पक्के आवास मिलने से गरीब परिवारों में धीरे-धीरे सामाजिक व आर्थिक बदलाव आ रहा है। उन्हें गंदगी से मुक्ति मिली साथ ही कच्ची छत गिरने का डर भी खत्म हो गया। लोग ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ रहे हैं। शुरुआती दौर के कई हितग्राही मजदूरी छोड़कर अब खुद का कारोबार करने लगे हैं। इस योजना से उनके जीवन में खासा बदलाव देखा जा रहा है। पीएम आवास प्लस योजना में जिले को प्रदेश में आठवां व संभाग में पहला स्थान मिला है।

कई हितग्राही मजदूरी छोड़कर धीरे-धीरे कारोबार से भी जुड़ रहे हैं। झिरन्या के रणजीत प्रेम सिंह डेहरिया कामा और गांव के निर्मल भंगी अब गांव में ही किराना व कटलरी का काम कर रहे हैं। वे बताते हैं पक्का मकान बनने के बाद अब कारोबार शुरू हो जाने से खुशी दोगुनी हो गई है। घर की आय बढ़ गई है। कमाई का बहुत सा हिस्सा पूंजी के रूप में एकत्रित होने लगा है।

1 लाख वां आवास बारिश में हर पल डर था अब नहीं

सेगांव जनपद के दसनावल की बिरोजा बाई पति काशीराम भालसे को पीएम आवास के तहत 100000 वीं हितग्राही बनाने का गौरव मिला है। वह बताती है कच्ची ईंट व गारे की जुड़ाई से मकान बना था। बारिश भी घर के भीतर प्रवेश कर जाया करती थी। डर भी ऐसा की कही पड़ोस में कुछ गिरने की आवाज अगर आती तो लगता था। कहीं दीवार या हमारा घर तो नही गिरा ? चोरी का डर खत्म हो गया। बारिश में अब घर में ही शौचालय भी है और 3 कमरे युक्त पक्का मकान। सरकार ने तो पक्के घर की चिंता दूर कर हैसियत भी बढ़ा दी है।

पीएम आवास प्लस में जिला संभाग में अव्वल

जिला पंचायत सीईओ ज्योति शर्मा बताती है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण 2016-17 में शुरू हुई अब तक एक लाख 1386 गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं। पीएम आवास प्लस योजना में जिले को राज्य स्तर पर आठवीं रैंक मिली। संभाग में प्रथम पर रहे है। जिले में 23894 पक्के मकान बनाये गए।

जिले में 15 वर्ष में 12 कलेक्टर और 11 एसपी का हुआ ट्रांसफर, आखिर क्यों...?

पटेल ने नवागत कलेक्टर और एसपी से भाजपा नेताओं से सावधान रहने की अपील की

माही की गूंज, अलीराजपुर।

बेतहाशा कर्जे में डूबी मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार का सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ताना बाना बुरी तरह सें बिगड़ गया है। प्रशासनिक अधिकारियों पर सत्ता पक्ष के भ्रष्ट हावी हो गए हैं। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव मे सत्ता परिवर्तन होना तय है, प्रदेश के जिलों से कलेक्टर और एसपी सत्तापक्ष के काम निकालने के लिए लगातार इधर सें उधर किए जा रहें हैं। उपरोक्त आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष नेता महेश पटेल ने कहा कि, 18 मई 2008 को नवीन जिले में एसपी जितेन्द्र कुशवाह आए, उन्हें मात्र 9 महीने में बदल दिया था। मात्र 15 वर्ष में 11 एसपी हो गए हैं ज़िले में, ज़िले की जनता हमसे पूछती हैं की ऐसा आख़रि क्यों हो रहा हैं। 17 मई 2008 से लेकर अब तक 12 कलेक्टर आ चुके हैं जिले में। उन्होंने बताया कि, रोचक तथ्य यह है कि सत्ता पक्ष की भ्रष्ट नीति प्रशासनिक अधिकारियों पर इतनी हावी है कि अलीराजपुर में प्रथम कलेक्टर के रुप में पारी शुरु करने वाले चंद्रशेखर बोरकर सर भाजपा राज में अफसरशाही करने के हालात ठीक नहीं होने के चलते अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं।

पटेल ने आरोप लगाया कि, जिले की सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों सहित भोपाल से नियंत्रित करने वाले राजनेता भी इस ट्रान्सफर के खेल में शामिल हैं। जो कलेक्टर और एसपी इस सुनियोजित भ्रष्टाचार में बदलाव करना चाहते हैं, यानि कम रेशियो में कमीशन ऊपर पहुचाते हैं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हैं। इन्हें अलीराजपुर जिले से बाहर निकाल दिया जाता हैं। वर्तमान में दोनों होनहार अधिकारी प्रमोशन प्राप्त करते हुए जिलाधिकारी बने हैं। सत्तापक्ष को लगता हैं की अपने भ्रष्टाचार में इनका उपयोग करने में आसानी से मदद मिलेगी। लेकिन जिले की जनता सब जान रही और समझ रही हैं। प्रदेश से अपना नियंत्रण खो रही सत्ता के जाने का वक्त आ गया हैं। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ आ रही हैं, भाजपा को अपनी भ्रष्ट नीति से विदा होना तय हैं । अब कोई अधिकारी भाजपा के भुलावे में न आए, ये अपना काम निकालकर चूसकर वल्लभ भवन या पुलिस मुख्यालय ट्रान्सफर कर देते हैं।

पटेल ने नवागत कलेक्टर और एसपी को आश्वस्त किया है कि, भाजपा नेताओं से सावधान रहकर ईमानदारी से जिले की आमजनता के हितार्थ काम करे, कल का सत्तापक्ष और आज का विपक्ष आपके साथ खड़ा हैं।

जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की खुल रही पोल

ग्रामीणों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना, मांग के बाद भी नहीं हुई सुनवाई

माही की गूंज, अलीराजपुर।

जिले के कट्ठीवाड़ा में एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है, जिसे देखने के बाद ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां पक्की सड़क न होने के चलते ग्रामीणों ने मरीज को झोली बनाकर अपने कंधे पर ढो कर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है।

ये है पूरा मामला

दरअसल कट्ठीवाड़ा के जैतपुर गाँव के गोपसिंह नामक शख्स की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। परिजन उसे निजी वाहन से स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए निकले, लेकिन कच्चे रास्ते पर कीचड़ की वजह से उनका वाहन बुरी तरह फंस गया। ऐसे में मरीज़ के परिजनों ने अन्य ग्रामीणों की मदद से कपड़े की एक झोली तैयार की और उसे झोली में डाल कर करीब 5 किमी अपने कंधों पर ढोया, जिसके बाद मुख्य मार्ग से पुनः उसे वाहन की मदद से कट्ठीवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया। ग्रामीणों द्वारा मरीज़ को झोली में काँधे पर धोने का यह वीडियो अब सामने आया है। वीडियो अपने आप में जिले के ग्रामीण अंचल में विकास की हक़ीक़त बयां करता है।

वर्षो से की जा रही है पक्की सड़क की मांग की

ग्रामीणों का आरोप है कि, कई वर्षो से यहाँ पक्की सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार उनकी एक नहीं सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में बारिश के दिनों में सड़क पर कीचड़ जमा हो जाने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि, कट्ठीवाड़ा ब्लॉक का जैतपुर गाँव गुजरात की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन पक्की सड़क न होने से अक्सर ग्रामीणों को कट्ठीवाड़ा पहुँचने के लिए गुजरात से होकर 25 किलोमीटर घूम कर सफर करना पड़ता है। जबकि जैतपुर गाँव से कट्ठीवाड़ा की दूरी महज़ 8 किलोमीटर ही है।

केवाईसी के कारण बैंक ने कर दिया था खाता लॉक, अब अकाउंट शुरू होते ही चैक क्लीयरिंग के नाम पर बैंक ने काट लिए खाते से रुपए

मामला बैंक ऑफ इंडिया का, खाताधारक ने मैनेजर को दिया आवेदन

आरबीआई के नियम के तहत खाताधारक मर्जी के बिना एक भी रुपया बैंक खाते से नहीं निकाल सकते

माही की गूंज, जोबट। अनिल हरवाल

इन दिनों बैंक ऑफ इंडिया जोबट की मनमर्जी से खाताधारक खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों के खाते तो केवाईसी के नाम पर लॉक कर दिए जाते हैं और कुछ के अन्य कारण बताकर, परेशान खाताधारकों को बैंकों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा हैं। बिना सुचना दिए पहले तो खाता लॉक कर दिया गया जब खाताधारक ने बैंक में जाकर संपर्क किया तो बताया गया कि केवाईसी के कारण आपका खाता लॉक है। जिसको लेकर खाताधारक ने सभी डॉक्यूमेंट जमा करवाएं जमा करने की कई दिनों बाद खाता पुनः शुरू हो पाया। लेकिन खाता पुनः शुरू होते ही बैंक ऑफ इंडिया जोबट के खाताधारक बालाजी ऑटो पार्ट्स के खाते से 354 रुपए क्लीयरिंग के नाम से निकाल लिए गए। खाताधारक ने इसकी शिकायत बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर प्रशांत गौतम से की तो मैनेजर ने आवेदन देने की बात कही उक्त खाताधारक ने सोमवार को पैसे कटने के बाद को लेकर मेनेजर को आवेदन दे दिया है अब देखना है कि उक्त राशि वापस खाते में आती है या नहीं।

मैसेज से पता चला कि पैसे काटे गए, फिर किया बैंक से सम्पर्क

बालाजी ऑटो पार्ट्स के खाताधारक को बीओआई के मेसेज से पता चला कि 354 रूपए काट लिये गये। उसके बाद सोमवार को खाताधारक ने बैंक पहुंचकर मेनेजर से जाना तो मेनेजर ने आवेदन देने कि बात कहीं।यहां पर बड़ा सवाल यह है कि बालाजी ऑटो पार्ट्स का खाता केवाईसी के कारण बैंक ऑफ इंडिया जोबट ने ही बंद कर रखा था। वो भी बिना किसी लिखित सुचना के उसके बावजूद भी बैंक ने अकाउंट से पैसे क्लिरियग के नाम से काट दिये, जो समझ से परे है।

प्रशांत गौतम मेनेजर बैंक ऑफ इंडिया जोबट ने कहा कि, लिखित में आवेदन दे दीजिए हम आगे मेल कर देते है।

वार्ड क्रमांक चार में हुआ नाली निर्माण का भूमिपूजन, कस्बे में अन्य स्थानों पर भी बनेगी नालियां

माही की गूंज, आम्बुआ।

आम्बुआ ग्राम पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 के निवासियों की विशेष मांग पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर आज सरपंच द्वारा भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत आम्बुआ क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में नाली निर्माण तथा मरम्मत कार्य की मांग पार्षदों द्वारा की गई है। इसका प्रस्ताव पंचायत द्वारा जनपद पंचायत अलीराजपुर भेजे जाने पर वहां से 10 लाख रुपए निर्माण कार्य हेतु जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता इंदर सिंह चौहान के अनुसंसा पर स्वीकृत किए गए। 29 जुलाई को ग्राम पंचायत सरपंच रमेश रावत तथा उपसरपंच थानसिंह भयडिया द्वारा वार्ड क्रमांक 4 में नाली निर्माण का भूमि पूजन किया गया।

सरपंच रमेश रावत ने बताया कि, कस्बे के अन्य वार्डों में भी मांग तथा जरूरत के हिसाब से नाली निर्माण कराया जाना है जो कि आगामी दिनों में कराया जाएगा। इस अवसर पर कस्बा काग्रेस अध्यक्ष हासिम अली बोहरा, आम्बुआ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमानुल्लाह पठान, मोहम्मद पठान, सारीक खान, विजय रावत, इंदरसिंह, राजेंद्रसिंह, मुस्तू बोहरा, असलम मकरानी, फिरोज खान, मांगू ठेकेदार आदि उपस्थित रहे।

सावन के चौथे सोमवार शिवालयों में उमड़ी भीड़, किया आकर्षक श्रृंगार

माही की गूंज, आम्बुआ। जगराम विश्वकर्मा

भूतभावन गौरपति आशुतोष भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह श्रावण जो कि इस बार अधिक मास के कारण और अधिक शुभ फलदायी माना जा रहा है, में उपासना हेतु शिवभक्त शिवालयों में पूजन अर्चन कर पुण्य प्राप्त करने में जुटे हैं। 3 वर्षों के अंतराल में अधिक मास आता है जिसे पहले मलमास कहा जाता था बाद में भगवान विष्णु ने इससे अपना नाम दिया तब से इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा है। इस बार पुरुषोत्तम मास श्रावण में पड़ने के कारण इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। क्योंकि पूर्व में श्रावण माह जो कि शिवजी को प्रिय माह रहता रहा है इस बार हरि-हर (विष्णु-शिव) के संयुक्त नाम का अधिक मास के कारण अधिक पुण्य दायी माना जा रहा है। एक माह की बजाय इस बार 2 माह तक शिव आराधना का पुण्य लाभ भक्तों को मिल रहा है। चार के स्थान पर आठ सावन सोमवार भक्तों की मनोकामना हेतु आने के कारण प्रत्येक शिव आराधक अधिक से अधिक भोले की भक्ति करना चाह रहा है। इसी कारण शिवालयों में सुबह से रात तक भक्तों का तांता लग रहा है। भागवत भूषण प्रख्यात शिव कथा प्रवक्ता गुरुदेव पंडित श्री प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की कथा का असर भी क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। सावन मास में उनके आव्हान पर एक लोटा जल की जगह दो लोटा जल बाबा को अर्पित किए जा रहे हैं। बिलपत्र आंकफूल, समीपत्र, गुलाब के फूल, काले तिल, चावल तथा गंगा जल, पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। आम्बुआ शिवालय में बाल शिव भक्त मंडल द्वारा भी प्रति शाम प्रदोष काल में भोलेनाथ की महाआरती की जा रही है। साथ ही नन्हे शिवभक्त सुबह बाबा का जल से अभिषेक कर रहे हैं। संपूर्ण क्षेत्र शिव भक्ति में लीन हो रहा है।

कावड़ यात्रियों का स्वल्पाहार के साथ किया भव्य स्वागत

माही की गूंज, आम्बुआ। सावन माह में भोले भंडारी की विभिन्न तरीके से पूजा-अर्चना कर उन्हें प्रसन्न कर मन वांछित फल प्राप्त करने का प्रयास शिव भक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांवड़ में जल भरकर सैकड़ों किलोमीटर शिवभक्त पैदल चल रहे हैं। ऐसे ही शिव भक्तों के कावड़ यात्री आम्बुआ से जब गुजरे तो उनका स्वागत भीलवट क्षेत्र में सरपंच तथा हनुमान मंदिर चौराहे पर संघ के कार्यकर्ताओं ने स्वागत के साथ स्वल्पाहार भी कराया।

मिली जानकारी के अनुसार अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद नगर के आस पास रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवक कांवड़ यात्री 160 की संख्या में मां नर्मदा का पावन जल ककराना से भरकर आजाद नगर की ओर जा रहे थे, जिनका भव्य स्वागत भीलवट बाबा प्रांगण में ग्राम सरपंच रमेश रावत, हासिम अली बोहरा, विजय रावत, गजेंद्र सिंह रावत आदि ने किया। आगे आने पर संकट मोचन दरबार हनुमान मंदिर चौराहे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया तथा स्वल्पाहार आदि कराया तथा यहां से आजाद नगर की ओर विदा किया एवं सुखद यात्रा की शुभकामना दी। स्मरण रहे कि, प्रतिवर्ष यहां से जितने भी कावड़ यात्री गुजरते रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्ता तत्परता के साथ यात्रियों का स्वागत कर स्वल्पाहार करा कर ही विदा करते हैं। यह परंपरा आज भी निर्वाहन की जा रही है।

मणिपुर में हिंसा के विरोध में संयुक्त मसीह समाज ने नयाब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, जोबट।

मणिपुर में बढ़ती हिंसा को लेकर पूरे देश मे विरोध स्वरूप अलग-अलग समाज, संघटन द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे है। इसी कड़ी में अलीराजपुर जिले के जोबट में संयुक्त मसीह समाज के बैनर तले एसडीएम के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। जिसमें बताया कि, मणिपुर में बढ़ती हिंसा को लेकर राज्य सरकार हिंसा को रोकने के लिए कोई कठोर कदम नही उठा रही है और न ही हिंसा पर काबू पाया जा रहा हे। महिलाओं व बच्चो पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मणिपुर शासन प्रशासन मुकदर्शक बना हुआ है। इसको लेकर विरोध स्वरूप आज सँयुक्त मसीह समाज के लोग हाथों मे तख्तियां लेकर रैली निकाल कर तहसील कार्यालय पहुँचे जहा राष्ट्पति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सोंपा गया और मणिपुर में सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इस मौके पर मसीह समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

उधर अंजू गई पाकिस्तान, इधर पिता को गंवाना ना पड़े मकान... !

ग्वालियर।

शादीशुदा अंजू अपने पूरे परिवार को छोड़कर पाकिस्तान चली गई है। अंजू के जाने से पूरे परिवार की जिंदगी बेपटरी हो गई है। पति रो-रोकर सभी को अपनी कहानी सुना रहा है। दो नाबालिग बच्चे हैं जो अब नहीं चाहते कि उनकी निर्मम मां वापस लौटे। भाई है जिसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और जिस पिता ने बेटी को जन्म दिया उसे अब लोगों की ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं कि वो टूट चुका है। अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस को अब गांव छोड़ने के लिए कहा जा रहा है।

गंवाना न पड़े मकान...!

अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहते हैं। बीते दिनो गया प्रसाद ने बेटी से बात करने के लिए कई बार कॉल किया। जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने वॉयस मैसेज भी भेजा। लेकिन बेटी का दिल नहीं पसीजा। गिड़गिड़ाते पिता की आवाज सुन भी उसने एक रिप्लाई नहीं दिया। अब उसी पिता के गांव वाले चाहते हैं कि वो गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं। 'आजतक' की रिपोर्ट के मुताबिक, गांव के लोगों का कहना है कि गया प्रसाद की बेटी अंजू की वजह से पूरे गांव की बदनामी हो रही है। ऐसे में वो उन्हें नया मकान (किसी और जगह) खोजने के लिए कह रहे हैं।

गांव वालों ने क्या-क्या कहा...?

गांव के लोगों ने कहा कि, अगर अंजू गांव में अपने पिता से मिलने कभी आएगी तो उसे गांव में घुसने ही नहीं दिया जाएगा। साथ ही उसे और उसके पिता को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं टूट चुके गया प्रसाद ने कहा कि इस तरह घुट-घुटकर रहना मुश्किल है। मेरा पूरा परिवार परेशान है। बता दें कि अंजू पाकिस्तान जाकर अब फातिम बन चुकी है। वहां के मीडिया का दावा है कि उसने इस्लाम धर्म अपना लिया है और अपने फेसबुक लवर नसरुल्ला से निकाह भी कर ली है।

पिता भी रडार पर

अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद उसके पिता भी जांच एजेंसियों की रडार पर आ गए हैं। ग्वालियर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं उनके सभी दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस गया प्रसाद के परिवार को लेकर सतर्क हो गई है। वहीं पिता का कहना है कि उनकी बेटी उनके लिए अब मर गई है।

पूरा मामला क्या...?

अंजू का कहना है कि, वो अपने पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्ला से मिलने गई है। लेकिन उसके वहां जाने के बाद ही ऐसी-ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आईं जिससे उसकी बातों पर कई तरह के सवाल उठने लगे। अंजू अपने परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही है। वहीं बीते दिनों उसने अपने पति अरविंद से कॉल पर बात की थी। वायरल कॉल रिकॉर्डिंग में सुना जा सकता था कि वो अरविंद को गंदी-गंदी गालियां दे रही थी। अरविंद ने कहा कि वो अब उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा।

जिले में फिर शुरू हुआ पुष्पा फिल्म की तरह काले तेल का गौरख धंधा, सीमावर्ती क्षेत्र में माफियाओं की हलचल बढ़ी

प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा अवैध व नकली डीजल का कारोबार, प्रशासन सबकुछ जानकर भी बन रहा अनजान

माही की गूंज, संजय भटेवरा

झाबुआ। वैसे तो मध्यप्रदेश के पश्चिमी छोर पर बसे आदिवासी बाहुल झाबुआ जिले में हमेशा ही अवैध धंधों की हलचल देखने को मिलती है। यह जिला शराब माफियाओं के लिए जन्नत साबित हुआ है। जिले में सबसे बड़ा अवैध धंधा शराब माफियाओं का ही है। मगर इसके अलावा भी कई ऐसे अवैध धंधे है जिनमें माफिया लगातार चांदी काट रहे है। चाहे जमीन से अवैध खनिज उत्खनन हो या अवैध रेत परिवहन, मादक पदार्थों की तस्करी हो या हाइवे के किनारे अवैध और नकली डीजल का विक्रय। इन सारे अवैध धंधों में माफिया लगातार सक्रिय ही रहे है। इस तरह के अवैध धंधों से माफियाओं की होने वाली काली कमाई का आंकड़ा करोड़ों में है। इसी अवैध अकूत काली कमाई के जरिये माफियाओं ने झाबुआ जिले को अपने कब्जे में कर रखा है। क्या शासन, क्या प्रशासन हर कोई माफियाओं की काली कमाई से टूकड़े तोड़ रहा है। यानी प्रशासन सब कुछ जानकर भी काली कमाई का माफियाओ से अपना हिस्सा लेकर अनजान बना रहता है। यही वजह है कि, जिला कभी माफ़ियाई राज से मुक्त नहीं हो पाया है। हां इतना जरूर है कि, अखबारों और मीडिया के खुलासे पर प्रशासन कार्यवाई का ढकोसला हमेशा से ही करता आया है। अहम ओहदों पर बैठे प्रशासनिक बागड़ बिल्ले कार्यवाही के बाद माफियाओं को कुछ समय भूमिगत होने की सलाह भी देते रहे है। सामान्य स्थितियों में माफिया फिर से सक्रिय होकर अपने अवैध धंधों को खुलेआम अंजाम देने लगते है।

माही की गूंज ने हमेशा से ही अवैध धंधों को अपने निशाने पर रखा है और लगातार इन माफियाओं के खिलाफ अपनी मुहिम को मजबूती से जारी रखा है। अवैध शराब की तस्करी हो या रेत माफियाओं का मकडज़ाल, नकली डीजल माफिया हो या किसी भी तरह का कोई अवैध करोबार माही की गूंज ने बेबाक तरीके से तमाम तरह के माफियाओं को बेनकाब करता आया है। माफियाओं और प्रशासनिक अधिकारियों के गठजोड़ भी लगातार उजागर किये है। जिसके चलते जिले के कई आला अधिकारियों, कलेक्टर और एसडीएम तक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हे जिले से रवानगी लेनी पड़ी है।

माही की गूंज की मुहिम और तत्कालीन अधिकारियों की रवानगी के बाद नकली व अवैध डीजल माफियाओं ने अपने अवैध धंधों पर विराम लगा दिया था। मगर अब फिर से जिले में अवैध और नकली डीजल में माफियाओं ने अपना फन फैलाना शुरू कर दिया है। पिछले लगभग एक-डेढ़ माह से गुजरात-मध्यप्रदेश सीमा पर जिले के सीमावर्ती इलाकों में यह डीजल माफिया सक्रिय दिखाई दे रहे है। रात के अंधेरे में शुरू हुआ काले तेल का यह गौरख धंधा अब दिन के उजाले में सरेआम अंजाम दिया जा रहा है। करीब एक-डेढ़ माह से रात में अपने धंधे को अंजाम देने वाले माफिया अब दिन दहाड़े अपने इस अवैध नकली डीजल के धंधे को खुले आम करते दिखाई दे रहे है। 24 घंटे लगातार चल रहे इस अवैध धंधे से माफिया जमकर चांदी काट रहे है। जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे 47 पर गुजरात सीमा के समीप बसा कस्बा पिटोल इन माफियाओं का अवैध धंधों का अड्डा शुरू से ही रहा है। बावजूद प्रशासन का इस और ध्यान नहीं देना कई सवालों को जन्म दे रहा है। अतिव्यस्त इस हाईवे पर हो रहे नकली अवैध डीजल के इस धंधे की खबर प्रशासन को नहीं हो यह तो हो ही नहीं सकता। इन माफियाओं के हौंसले देखकर तो यही लग रहा है कि, प्रशासन और माफियाओं के बीच फिर से गोटी फीट हो चुकी है।

पिटोल के समीप नेशनल हाईवे पर मामा-भानेज ढाबे के समीप इन अवैध नकली डीजल माफियाओं ने वर्तमान में अपना अड्डा बना रखा है। पहले भी इसी ढाबे के आसपास माफिया अपने अवैध नकली डीजल के धंधे को संचालित करते रहे है। पूर्व में यहां माफियाओं ने प्रशासनिक गठजोड़ के चलते इतनी हिमाकत की थी कि, लायसेंसी डीजल-पेट्रोल पंपों की तरह जमीन में अवैध टेंक गाढ़कर मशीने लगा दी थी और लायसेंसियों की तरह ही जमकर अवैध धंधा किया था। ततसमय जिले से गुजरने वाले पूरे नेशनल हाइवे पर लगभग एक दर्जन बायो के नाम से अवैध व नकली डीजल के ठीये माफियाओं ने खोल डाले थे। जिससे राज्य शासन को करोड़ों रुपये की राजस्व की हानी हुई थी और लायसेंसी डीजल-पेट्रोल पंपों को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा था। इन माफियाओं की वजह से लायसेंसी डीजल-पेट्रोल पंपों पर डीजल का उठाव लगभग न के बराबर रह गया था। माही की गूंज के जरिए जब मामला उजागर होकर सुर्खियों में आया तो तत्कालीन प्रशासन ने दबाव में आकर जिले में चल रहे तमाम अवैध और नकली डीजल के ठीकानों को बंद करवा दिया था। पहले गुजरात का रेत माफिया युसूफ जिले में नकली डीजल के इस अवैध धंधे को लेकर आया था और उसके बाद तो जैसे डीजल माफियाओं की बाढ़ आ गई थी। हर माफिया जैसे नकली डीजल के इस अवैध धंधे में हाथ आजमाने को आतुर हो गया था। जिसमें पिटोल के शराब माफिया और होटल संचालक अज्जू-विज्जू ने भी इस नकली तेल के काले धंधे में अपने हाथ काले किए थे।

एक बार फिर इन नकली डीजल माफियाओं ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है। अब वर्तमान में भी एक रेत माफिया अपने रेत के अवैध धंधे को छोड़कर नकली तेल के इस अवैध धंधे में कूद पड़ा है। नाम है गुल्लु। आलीराजपुर-झाबुआ जिले में रेत के अवैध करोबार का सरगना रहा गुल्लु पिछले कई सालों से रेत के अवैध परिवहन और रेत माफियाओं से उगरानी में संलिप्त रहा। दोनों जिलों में इस माफिया को खूब राजनीतिक संरक्षण मिला। अपने अवैध धंधे से माफिया ने अपने आकाओं की खूब सेवा चाकरी भी की। मगर राजनीति गर्माने के बाद गुल्लु ने रेत के अवैध धंधे से अपने हाथ धीरे-धीरे खींच लिए। मगर कहते है कि, ''चोर चोरी से जाए पर हेरा-फेरी से ना जाए'' तो गुल्लु ने आलीराजपुर के एक भाजपाई नेता के साथ नकली डीजल के अवैध धंधे की शुरूआत कर दी। काफी समय तक आलीराजपुर जिले की गुजरात सीमा को इसने अपना अवैध धंधों का अड्डा बनाया मगर विपक्षी राजनीकि प्रभावियों से पंगे लेना गुल्लु को भारी पड़ गया। जिसके बाद गुल्लु ने अपने नकली डीजल के अवैध धंधे को समेट कर गुजरात सीमा में प्रवेश कर लिया, लेकिन यहां भी गुल्लु की दाल नहीं गल रही। बताया जाता है कि, अपना सारा अवैध नकली डीजल का कारोबार आलीराजपुर से समेट कर गुजरात सीमा में प्रवेश करने के बाद भी माफिया के हाथ खाली ही नजर आए। गुजरात में इस तरह के नकली डीजल पर सख्ती से प्रतिबंध लगा हुआ है। अब इस नकली डीजल माफिया ने झाबुआ जिले के पिटोल को अपना अड्डा बना लिया। बताया यह भी जाता है कि, इस गौरख धंधे में गुल्लु अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ इसका कोई पार्टनर भी है। पिछले काफी समय से पिटोल बायपास पर मामा-भानेज ढाबे के समीप से गुल्लु अपने इस नकली डीजल के अवैध धंधे को रातों में अंजाम दे रहा था, लेकिन अब उसका यह अवैध धंधा दिन दोगुनी और रात चोगुनी तरक्की कर रहा है।

सुत्र बताते है कि, जिस वाहन से इस अवैध नकली डीजल की खपत की जा रही है वह आयसर का छः पहियां टेंकर है। जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर जीजे 01 जे टी 1399 अंकित है। जिसकी क्षमता लगभग 12 हजार लीटर की है। बताया यह भी जा रहा है कि, 24 घंटे में यह पूरा नकली डीजल माफिया खपा देते है। शातिर माफिया ने इस टेंकर को इस तरह से डीजाईन करवाया है कि, इसके पिछले हिस्से में ही डीजल नापने की मशीन लगा दी है। ये वैसा ही है जैसा एक बॉलीवुड मुवी पुष्पा में दूध के टेंकर में पुष्पा भाउ को चंदन की तश्करी करते हुए दिखाया गया है। ठीक वैसे ही माफिया ने 12 हजार लीटर के टेंकर में पीछला हिस्सा खोखला रखकर उसमें डीजल मापने व भरने की मशीन लगा रखी है। कुल मिलाकर इस 12 हजार क्षमता वाले टेंकर में 10 हजार लीटर डीजल भरा होता है और बाकी के हिस्से में मशीन फीट की हुई है। माफिया ने अपने अवैध धंधे को छुपाने के लिए युरिया की दुकानदारी भी वहीं खोल रखी है जो उसके अवैध धंधे को आड़ मिल जाती है। रोड़ से देखने पर यह लगता ही नहीं कि, यहां कोई अवैध डीजल का धंधा चल रहा है। चूंकि आजकल वाहनों में यूरिया का उपयोग भी फ्यूल के रूप में किया जा रहा है तो यूरिया के बड़े-बड़े बोर्ड और बड़े-बड़े टेंक माफिया ने अपने अवैध धंधे की आड़ के लिए लगा रखे है। मगर बावजूद इसके माफिया के सारे ग्राहक टेलीफोनिक संपर्क के जरिए उसके ठिकानें तक पहुंच ही जाते है।

वर्तमान में 10 रुपये से ऊपर के नेट प्रोफीट के हिसाब से 1 लाख रुपये ज्यादा रोज की अवैध और अकूत कमाई माफिया कर रहा है। इससे राज्य शासन को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान इस तरह हो रहा है कि, कई वाहन मालिक लायसेंसी डीजल पंप से डीजल ना भरा कर अपने वाहनों में नकली और सस्ता डीजल इस्तेमाल में ला रहे है। कारण यह है कि, यह ओरिजनल डीजल से काफी सस्ता पड़ता है। जिससे वर्तमान में वाहन मालिकों को फायदा हो रहा है, लेकिन इसके दुरगामी परिणाम काफी घातक है। इस तरह के नकली डीजल से वाहन के इंजन की उम्र घटकर लगभग आधी ही रह जाती है। वाहन मालिक की मर्जी नकली डीजल डलाने की ना भी हो तो ड्रायवर और क्लिनर अपनी जेबें गर्म करने के लिए इस तरह के नकली डीजल का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते है। फिर चाहे वाहन मालिक को नुकसान ही क्यों न हो।

अब जब कि, माही की गूंज इस तरह के नकली डीजल माफिया का खुलासा कर रहा है तो फिर देखने वाली बात यह भी होगी कि, अब प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है। अगर प्रशासन इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता है तो यह तय माना जाएगा कि, माफिया की प्रशासनिक अमले के बागड़बिल्लों से सेटिंग हो चुकी है और वह अपनी अवैध अकूत कमाई से कुछ टुकड़े प्रशासनिक बागड़ बिल्लों को भी डालता है।

अतिआत्मविश्वास के घेरे में निर्मला भूरिया, कार्यकर्ताओ से दूरी पड़ रही है भारी

निर्मला भूरिया के नाम को लेकर बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं में नही बन पा रही सहमति

भाजपा के लिए संगठन के बल पर मैदान में उतरने की एक मात्र सीट

माही की गूंज
पेटलावद ,राकेश गेहलोत

पेटलावद विधानसभा सीट के लिए लगातार मंथन संगठन में जारी है। इस बार इस सीट से भाजपा की ओर से एक-दो नही कई चेहरे सामने आ चुके है, जो पूरी ताकत से मैदान में दावेदारी को लेकर जुटे है। इस सीट से पिछले चार से पांच चुनाव में प्रबल दावेदार रह कर चुनाव मैदान में उतर चुकी। पूर्व विधायक निर्मला भूरिया इस बार भी पूरी तरह आश्वस्त है इस बार भी भाजपा की ओर से चेहरा वही होगी और उनके अलावा भाजपा के पास कोई चेहरा नही जिसके दम पर मैदान में उतर सके।

अतिआत्मविश्वास के चलते कार्यकर्ताओं से दूरी

विधानसभा क्षेत्र 195 भाजपा के लिए अन्य सीटो के मुकाबले कम मुश्किल में रही है। यहां हार-जीत का अंतर 5 से 10 हजार तक रहा है और आज से पहले तक इस सीट पर निर्दलीय चेहरे कभी इतने हावी नही रहे कि, स्वयं के दम पर दस हजार का आंकड़ा पार कर सके। पूर्व विधायक निर्मला भूरिया इस सीट से चुनाव मैदान में उतरने को लेकर अति आत्मविश्वास के घेरे में है जिसके चलते उनको लगता है कि, भाजपा के पास उनके अलावा और कोई ऑप्शन नही है और इसी अति आत्मविश्वास के चलते निर्मला भूरिया ने कार्यकताओं से दूरी बना रखी है। निजी तौर पर निर्मला भूरिया की कोई तैयारी जमीनी स्तर पर नजर नही आ रही। बहारी विस्तारकों के द्वारा पार्टी द्वारा करवाये गए सर्वे में भी ये सामने आ चुका है कि, इस बार भाजपा के कार्यकर्ता परिवर्तन चाहता है।

संगठन के दम पर मैदान में उतरने के लिए भाजपा के लिए एक मात्र सीट

पेटलावद विधानसभा की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो भाजपा संगठन के लिए परिवर्तन कर प्रत्याशी मैदान में उतारने के लिए जिले की सबसे मजबूत सीट है। जिले की दो अन्य सीट थांदला और झाबुआ में भाजपा स्थानीय स्तर पर प्रभावी और सक्षम प्रत्याशी के दम पर मैदान में उतरना मजबूरी है, लेकिन पेटलावद विधानसभा के भाजपा संगठन के दम पर किसी भी जमीनी नेता को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतर सकती है। भाजपा सहित कांग्रेस और जयस जैसे संगठनों की ओर से स्थानीय प्रत्याशी की आवाज बुलंद हो रही है और आम जनता भी इस मांग से सहमत दिखती नजर आ रही है। जनता की नस को पकड़ कर मैदान में उतरने वाले दल को फायदा होना तय है। उधर इस सीट से मैदान में उतरने के लिए तैयारी में जुटे कई प्रत्याशियों द्वारा बार-बार पार्टी के द्वारा एक ही व्यक्ति को लगातार मौका देने का विरोध उपज रहा है जो भाजपा के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।

निर्मला व डामोर के नाम पर निराशा का माहौल

लगातार 5 चुनाव से इस सीट से मैदान में उतर रही निर्मला भूरिया की दावेदारी को लेकर कार्यकर्ताओ में भारी निराशा का माहौल है। वही इसी क्षेत्र से मैदान में उतरने की कोशिश में सांसद डामोर को लेकर स्थानीय स्तर पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। आम चर्चा के दौरान भाजपाई खुलकर इन दोनों नाम पर असहमति जताते हुए नए चेहरे को खुलकर मैदान में उतरने के दावे कर रही है। भाजपा के लिए इस बार का चुनाव वर्ष 2018 के चुनाव से भी मुश्किल हैं जहां सत्ता से बाहर होने का स्वाद चख चुकी है। कई अलग-अलग सर्वे में भी इस बार प्रदेश में कड़ा मुकाबला भाजपा-कांग्रेस के बीच होना है। ज्यादातर सर्वे में भाजपा फिर से बहार होती दिख रही है ऐसे में भाजपा उन मुख्य सीटो पर जहा से भाजपा मजबूत है उनके पेटलावद विधानसभा भी एक है वहा पर पूरी योजना के साथ मैदान में उतरने की कोशिश करेगी।

वालसिंग व मालू की सक्रियता ने बड़ा दी भाजपा की चिंता

भाजपा आकड़ो के अनुसार इस सीट पर भले मजबूत हो लेकिन पिछले चार में से दो चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इस बार भाजपा की तरह कांग्रेस में टिकिट के लिए दो मजबूत चहरे मैदान में है और टिकिट की मारा-मारी के बीच पिछले 6 माह से पूर्व विधायक वालसिंह मेड़ा और जिला पंचायत उपाध्यक्ष मालू डामर लगातार कांग्रेस के लिए सक्रिय है। कई भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के खेमे में चले गए तो नए चेहरे के नाम पर मालू डामर सबसे ज्यादा समर्थन जुटाते दिख रहे है। न केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा और जयस जैसे संगठन के कार्यकर्ता मालू के समर्थन में आकर काम कर रहे है। अब तक कमजोर दिख रही कांग्रेस का दो तरफा हमला भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। क्योंकि चुनाव में विधायक और जिला पंचायत उपाध्यक्ष दोनों में से एक कांग्रेस की ओर से मैदान में उतरने की स्थिति में भाजपा के लिए परेशानी खड़ी होना तय है।

पटवारी हल्का नम्बर 1 में सरकारी भूमियों को निजी बनाने का चल रहा खेल

शिकायत के बाद भी शासन खुद की भूमि नहीं करवा पा रहा मुक्त

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद विकास खण्ड में लगातार बेशकीमती सरकारी भूमि को राजस्व रिकॉड में हेरा-फेरी कर निजी बनाने की शिकायत दर्ज हो रही है। शिकायत के बाद स्थानीय राजस्व विभाग स्वयं की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से न तो मुक्त करवा पा रहा है न ही हेरा-फेरी करने वालो पर कोई बड़ी कार्रवाई कर पा रहा है। जिससे सरकारी भूमि को कब्जाने वाला सिंडिकेट एक के बाद एक सरकारी भूमि को हड़प कर निजी बनाने में कामयाब हो रहा है। आलम ये है कि, किसी शासकीय भवन के निर्माण के लिए सरकारी भूमि की आवश्यकता होने पर जमीन ऐसे इलाको मिलती है जहां कोई सुविधा नही होती और अगर कोई भूमि नगरीय क्षेत्र या मुख्य मार्गो से लगी भूमि पर रेकॉर्ड अनुसार सरकारी भवन स्वीकार होने पर जमीन पर कब्जा और अतिक्रमण कर रजिस्ट्री होने के मामले सामने आते है, जो न्यायालय में उलझ कर निर्माण नही होता। विकास खण्ड के ग्राम पंचायत बामनिया और पटवारी हल्का क्रमांक 1 के गांव रामपुरिया, मुल्थानीया की मुख्य रोड से लगी और उसके आस-पास की सरकारी भूमि पर भू-माफियाओ की ऐसी काली नजर पड़ी की ज्यादातर सरकारी भूमि किसी न किसी प्रकार से हतिया ली गई है। सबसे बड़ी बात यहा इन सरकारी भूमियों को लेकर पुराने रेकॉर्ड के साथ प्रमाणित शिकायते दर्ज हुई लेकिन कोई कार्रवाई नही की जाती और मामला एसडीएम न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट के नाम पर उलझा दिया जाता। किन्ही प्रकरणों में बमुश्किल सरकारी पाई गई भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के आदेश जारी होने के बाद भी अतिक्रमण से न तो मुक्त करवाई जाती है, न ही हेरा-फेरी करने वालो के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है।

फिर हुई शिकायत

ताजे मामले में ग्राम मुल्तानिया में बामनिया-पेटलावद मार्ग पर गोया मद (जानवरों के लिए विश्राम स्थल) की भूमि पर प्लाट काटे जा रहे हैं। इसकी शिकायत कुछ दिन पहले कलेक्टर से भी की गई है। शिकायतकर्ता श्रवण मालवीय ने फर्जी रजिस्ट्री का आरोप लगाते हुए सरकारी भूमि की रजिस्ट्री कराने वाले वेंडर पेटलावद उपपंजीयक एवं पटवारी पर धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करने की मांग भी की है। शिकायतकर्ता ने बताया कि, पटवारी हल्का नंबर मुल्तानिया के नाम से दर्ज भूमि जो सर्वे नंबर (1) 324 रकबा 1-10, 0-445, (2)327 रकबा 125, 0-506, (3) , 328 रकबा 1-60, 0-647, (4) 345-रकबा 1, 81, 0-732 पेटलावद रोड स्टेट हाईवे के पास बामनिया से आने की तरफ और पेटलावद से जाने की तरफ स्थित है। रिकॉर्ड में दर्ज भूमि जानवरों के विश्राम स्थल के नाम से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। इस भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जिन्होंने हल्का पटवारी की मिली भगत से गोया की भूमि की रजिस्ट्री पेटलावद वेंडर तथा उपपंजीयक रजिस्ट्रार से करवा ली है। रजिस्ट्री करने के बाद इस बेशकीमती भूमि को बेच दिया है और खरीददार ने इस जगह पर कब्जा जमा लिया है। जिन व्यक्तियों द्वारा आदिवासी तथा गैर आदिवासी व्यक्तियों को निजी भूमि की आड़ में रजिस्ट्री कराई गई है उन व्यक्तियों को शासन ने काश्तकारी के रूप में जीवन यापन करने के लिए पट्टा दिया है, पट्टा धारियों द्वारा भी आदिवासियों तथा गैर आदिवासियों की चारों सर्वे नंबर के आसपास की जमीन बेच दी गई है। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है।

इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से जांच कर इस भूमि पर काबिज व्यक्तियों को नोटिस जारी कर विधिवत पुराने रिकॉर्ड, खसरा-खतौनी ,खसरा पाचशाला ,नक्शा वर्ष 1959 से वर्ष 1974 तक रिनंबरिंग सूची के आधार पर पटवारी हल्का नंबर 1 बामनिया तथा मुल्तानिया की भूमि का सीमांकन करने की मांग की है। और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

कोर्ट के आदेशो की अवेहलना का आरोप

उधर ग्राम पंचायत बामनिया के रतलाम रोड स्थित शासकीय सर्वे नम्बर 105,106 और 107 को लेकर शिकायत ओर जॉच का कोई निराकरण नही हुआ। शिकायतकर्ता और भूमि पर कब्जा कर, रजिस्ट्री कर बेचने व खरीदने वाले हाईकोर्ट की शरण में पहुँच गए। जहा से मिले समय के बाद भी कलेक्टर कार्यालय से कोई निराकरण नही हुआ। इससे पूर्व शिकायत का दायरा छोटा करते हुए पूरी सरकारी भूमि की नपती करने की बजाए कुछ भूमि को ही दायरे में लिया गया और अब मामला अतिक्रमण ओर वो भी एमपीआरडीसी की भूमि पर होना बताने का प्रयास कर मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। शिकायतकर्ता श्रवण मालवीय ने बताया कि, इस मामले में कोर्ट के आदेशों की अवेहलना की शिकायत सम्बंधित अधिकारीयो के विरुद्ध करेंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422